सुविचार

प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है।
-रवींद्रनाथ टैगोर

Daily

सच के हक में...

THE PHOTON NEWS

द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

12

Sunny Leone Turns Airport Into A...

Ranchi ● Saturday, 23 August 2025 ● Year : 03 ● Issue : 218 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पहला अनुपूरक बजट पेश

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में बताया कि यह अनुपूरक बजट उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाया गया है, जो मुख्य बजट में शामिल नहीं हो सकीं या जिनके लिए अतिरिक्त धन की जरूरत महसूस की गई। इस अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को गति देना और जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना है। इसके बाद सदन में शोक प्रकट किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4296 करोड़ से अधिक का पेश किया अनुपूरक बजट

शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास से जुड़ीं योजनाओं के लिए किए गए हैं प्रावधान

दिवंगत हस्तियों को दी गई श्रद्धांजलि

मानसून सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन ने गुरुजी शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, दिवंगत राज्यपाल सतपाल मालिक और पत्रकार हरिनारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिशोम गुरु और शिक्षा मंत्री के प्रति श्रद्धांजलि दी। जानकारी के अनुसार, 25 अगस्त को विधानसभा से गुरुजी को भारतरत्न देने का प्रस्ताव पारित होगा। इसके अलावा, सदन में 26 अगस्त को अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा होगी।

25 अगस्त को विधानसभा से गुरुजी को भारतरत्न देने का प्रस्ताव हो सकता है पारित

गुरुजी को भारतरत्न देने के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन बोले- यह राज्य की जनता का भाव

शोक प्रस्ताव के दौरान पक्ष और विपक्ष सभी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उन्होंने सदन में शिबू सोरेन को भारतरत्न देने की जोरदार मांग की है। प्रदीप यादव ने सदन से आग्रह किया कि विधानसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। कहा कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न के लिए शिबू सोरेन से बड़ा कोई पात्र नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के योगदानों को देखते हुए उन्हें भारतरत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। शिबू सोरेन ने झारखंड के अधिकारों, आदिवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सदन की भावना है। राज्य की जनता का भाव है, उसे सदन में सदस्यों ने रखा। इस पर सदन विचार करेगा।

बजट की फैक्ट फाइल

शिक्षा और स्वास्थ्य : बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए, अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।

बुनियादी ढांचा: बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

ग्रामीण विकास : ग्रामीण विकास के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

सामाजिक सुरक्षा : सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

SHARE

सेंसेक्स	:	81,306.85
निफ्टी	:	24,870.10

SARAFA

सोना	:	9,380
चांदी	:	128.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

उत्तर पश्चिमी जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

RANCHI : मौसम विभाग ने 23 अगस्त को भी झारखंड के उत्तर पश्चिम जिले पलामू,गढ़वा, लातेहार, चतरा जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न स्थानों में अगले पांच दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने भारी होने को लेकर लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को बताया कि भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। साथ ही कहा कि बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर सकता है। इससे मिट्टी के घर या सीट के घर गिर सकते हैं। साथ ही लगातार बारिश से गीली मिट्टी होने के चलते पेड़ गिरने से दुर्घटना होने की भी आशंका है।

बिहार को प्रधानमंत्री मोदी ने दी कई सौगातें, जनसभा को किया संबोधित

चुन-चुनकर सभी घुसपैठियों को निकालेंगे देश से बाहर : पीएम

GAYA @ PTI : शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी से बिहार के लिए 13 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बदल रही जनसांख्यिकी का मुद्दा उठाया। इस संबंध में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और वाम दलों पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह दल बिहार के लोगों का अधिकार घुसपैठियों को देना चाहते हैं। हम, घुसपैठियों को लोगों के अधिकारों पर डाका डालने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लाल किले के अपने भाषण में घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए बनाए जा रहे डेमोग्राफिक मिशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से चुन-चुनकर सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा।

सीमावर्ती इलाकों में बदल रही जनसांख्यिकी के मुद्दे को जोर-जोर से उठाया

- पीएम ने 13 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास
- लोगों के सामने कांग्रेस, राजद और वाम दलों के वोटबैंक पॉलिटिक्स पर साधा निशाना
- प्रधानमंत्री ने संसद में पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक का भी किया उल्लेख
- स्पष्ट किया- भ्रष्टाचार करने वाला जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी

जमानत नहीं मिलने पर छोड़ना पड़ेगा पद

मोदी ने कहा, एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी आता है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल किए गए हैं। इस कानून के बनने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि संविधान हमसे ईमानदारी और पादर्शिता की मांग करता है।

ऑपरेशन सिंदूर देश की रक्षा नीति में नई लकीर

ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। इसी धरती से लिया संकल्प पूरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर ने देश की रक्षा नीति में एक नई लकीर खींच दी। अब कोई भी आतंक फैलाकर बच नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है। वहीं लालटेन (राजद का चुनाव चिह्न) के राज में बिहार लाल आतंक से घिरा था।

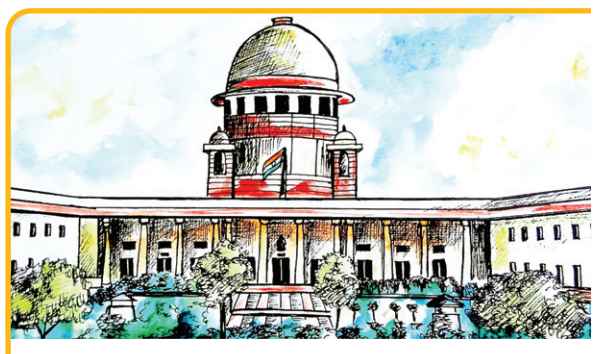

वोटर वेरिफिकेशन के लिए 'आधार' को मान्य करने का 'सुप्रीम' आदेश

NEW DELHI @ PTI : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) को आदेश दिया कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई। पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको आगे आना चाहिए। अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजनीतिक दलों से से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहां मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई हैं। वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं।

लिस्ट में नाम जुड़वाने को ऑनलाइन भी आवेदन दे सकेंगे हटाए गए वोटर्स

- मतदाताओं की मदद को लेकर कोर्ट ने राजनीतिक दलों को भी लगाई फटकार
- इस मामले की जारी रहेगी सुनवाई, अब 8 सितंबर को होगी अगली हियरिंग

तीन शहरों के लिए सरकार ने भेजा था प्रस्ताव

रांची को मिलेगी मेट्रो की सौगात केंद्र ने मांगी सीएमपी रिपोर्ट

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। इस योजना के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की जरूरत कितनी है और किस मार्ग पर इसका संचालन संभव है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद केंद्र ने केवल रांची को लेकर सीएमपी रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। बता दें कि रांची में लगातार वाहनों की संख्या और यातायात जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। मेट्रो से राहत पहुंचने की उम्मीद है।

चार से 13 अगस्त तक 24 घंटे वाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार रखी नजर, 13 किस्तों में ठगे रुपये

दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 27 लाख की ठगी

PHOTON NEWS ASANSOL : डिजिटल अरेस्ट को लेकर बार-बार जागरूकता के बावजूद लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हीरापुर थाना अंतर्गत आसनसोल के रवींद्र नगर स्थित डॉली लॉज इलाके में एक व्यक्ति से एक करोड़ 27 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित तपन कुमार माजी ने आरोप लगाया है कि साइबर अपराधियों ने उन्हें डिजिटल तरीके से गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस और सीबीआई बताकर एक करोड़ 27 लाख 4,332 रुपये की ठगी की है। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले जून में आसनसोल नगर निगम के पूर्व सहायक अभियंता सुकुमार दे को साइबर अपराधियों ने 32 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके 1.65 करोड़ रुपये लूट लिए थे।

जून में एक अधिकारी से 32 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर लूट लिए थे 1.65 करोड़

आधार नंबर का उपयोग कर मुंबई में खोला खाता

तपन कुमार माजी के अनुसार 4 अगस्त को सुबह लगभग 10.30 बजे एक नंबर से राहुल राय डीजीसीए कहते हुए फोन आया। फोन पर बताया गया कि मुंबई में उनके आधार नंबर का उपयोग करके केनरा बैंक में एक खाता खोला गया है। इसमें दो करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है। उन्हें बताया गया कि यह सिम कार्ड व रुपये अवैध गतिविधियों और मनी लांड्रिंग में शामिल हैं। इसके बाद एक अज्ञात मोबाइल नंबर से वाट्सएप कॉल आया। इसमें कहा गया कि वे मुंबई पुलिस से हैं। उन्होंने अपनी मुंबई पुलिस की आईडी दिखाई और वे पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। उसने कहा आतंकवाद की फंडिंग के लिए भी रुपये का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद उसने धोखाधड़ी वाले बैंक खाते का स्टेटमेंट और डेबिट कार्ड की तस्वीर भेजी। यह भी कहा कि उन्हें मनी लांड्रिंग के मामले में डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया है।

ईडी का गिरफ्तारी वारंट भी भेजा

डिजिटल अरेस्ट करने वाले ने प्रवर्तन निदेशालय से गिरफ्तारी वारंट, भारतीय रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट के कुछ दस्तावेज भी भेजे। फिर वीडियो कॉल पर पुलिस वर्दी पहने एक व्यक्ति को दिखाकर डराया। उस व्यक्ति ने चार अगस्त से 13 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट कर 24 घंटे वाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार नजर रखकर डराया और कुल 1,27,04,332 रुपये 13 किश्तों में ले लिया। ठगी का अहसास होने पर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई

RANCHI : झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एनवी अनजारिया की पीठ में सुनवाई हुई। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मुद्दे पर जारी सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही याचिकाएं दायर है। यह नियम संगत नहीं है। एक साथ दोनों जगह याचिका दायर होने का मामले उठने के बाद एमिकस क्यूरी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय से यह अनुरोध किया कि झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका 1194/2025 की सुनवाई करने का फैसला किया।

बड़ी पहल | आईसीएमआर ने तैयार किया एक समान मूल्यांकन वाला प्रोटोकॉल

चिकित्सा क्षेत्र में घटिया जांच उपकरणों से जल्द मिलेगी मुक्ति

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : भारत के चिकित्सा क्षेत्र में मोदी सरकार ने लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने न केवल आयुष्मान भारत जैसी योजना को कार्यान्वित किया है, बल्कि चिकित्सकीय जांच की प्रणाली को भी गुणवत्तापूर्ण रखने पर फोकस किया है। विभाग के हाल के फैसले के मुताबिक, देश में घटिया किस्म के जांच उपकरणों पर अब जल्द रोक लग जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) किट्स की गुणवत्ता और भरोसेमंद के लिए एक मूल्यांकन प्रोटोकॉल तैयार किया है। इस कदम से विभिन्न तरह की जांच किट्स जैसे इन्फ्लूएंजा, सार्स-कोव-2 और आरएसवी की सटीकता और प्रभावशीलता की जांच को मानकीकृत करने की दिशा में तैयार किया है। मसौदे में स्पष्ट है कि अभी इसका दायरा श्वसन संबंधी बीमारियों की जांच किट्स तक सीमित रहेगा, जिसमें इन्फ्लूएंजा वायरस, कोविड-19 और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस (आरएसवी) की पहचान के लिए बनाए गए सिंगल या मल्टीप्लेक्स टेस्ट शामिल हैं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भी इस कार्य में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

अभी इसका दायरा श्वसन संबंधी बीमारियों की जांच किट्स तक रहेगा सीमित

- इन्फ्लूएंजा, सार्स-कोव-2 व आरएसवी की जांच में आएगी सटीकता और प्रभावशीलता
- एक जैसा मानक न होने की वजह से परीक्षणों की विश्वसनीयता पर पड़ा असर
- आईवीडी उत्पाद को बाजार में लाने से पहले परखी जाएगी संवेदनशीलता और विशिष्टता

गलत नतीजों के कारण होने वाली दवा की बर्बादी और मरीजों की परेशानी होगी कम

बड़ी संख्या में बाजार में आई जांच किट्स

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में जांच किट्स बाजार में आईं। इनमें से कई की गुणवत्ता पर सवाल उठे और राज्यों से गलत नतीजों की शिकायतें भी सामने आईं।

वैज्ञानिकों और उद्योग जगत से मांगे गए सुझाव

विशेषज्ञ मानते हैं कि एक समान मानक न होने के कारण परीक्षणों की विश्वसनीयता पर असर पड़ा। इसी के चलते अब यह नया प्रोटोकॉल बनाया गया है, ताकि किसी भी आईवीडी उत्पाद को बाजार में लाने से पहले उसकी संवेदनशीलता, विशिष्टता और प्रदर्शन का एक समान पैमाने पर मूल्यांकन हो। फिलहाल आईसीएमआर ने मसौदे पर उद्योग जगत, वैज्ञानिकों और नीति विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मसौदे को लागू करने के बाद भारत में आईवीडी किट्स के लिए एक सुनियोजित नियामक ढांचा खड़ा हो जाएगा। इससे जहां आम मरीजों को सही और समय पर निदान मिलेगा, वहीं कंपनियों के लिए भी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के नए अवसर खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मानकीकृत मूल्यांकन से रोगों की पहचान अधिक सटीक होगी।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे अरेस्ट

NEW DELHI : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह शामिल होने लंदन गए थे। इसके लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन पर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भी सरकारी खजाने से सैलरी देने का आरोप है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि विक्रमसिंघे आज सुबह वित्तीय अपराध जांच विभाग (एफसीआईडी) में इस मामले से जुड़ी पूछताछ के लिए पहुंचे थे। एफसीआईडी ने उन्हें कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे श्रीलंकाई इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। विक्रमसिंघे ने 2023 का क्यूबा का दौरा किया था।

महिला जज को हजारीबाग में ही रहने दें या बोकारो कर दें ट्रांसफर : सुप्रीम कोर्ट

RANCHI : हजारीबाग की एक महिला जज के ट्रांसफर मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को नसीहत दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को अपने न्यायिक अधिकारियों के माता-पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय से कहा कि वह एकल अभिभावक महिला न्यायिक अधिकारी को हजारीबाग में ही रहने दे या उनके बेटे की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोकारो ट्रांसफर कर दे। पीठ ने कहा, उच्च न्यायालयों को अपने न्यायिक अधिकारियों की समस्याओं के प्रति सजग रहना होगा। महिला न्यायिक अधिकारी ने 6 महीने के बाल देखभाल अवकाश के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। बाद में उनका तबादला दुमका कर दिया गया। महिला न्यायिक अधिकारी ने झारखंड हाईकोर्ट से अपील की कि उन्हें हजारीबाग में सेवा जारी रखने दिया जाए या उनका रांची अथवा बोकारो ट्रांसफर कर दिया जाए।

चतरा में बारिश का कहर, घर ढहने से पति-पत्नी की मौत

लगातार वर्षा से आई बाढ़ में कई मवेशी भी बहे

बाढ़ में डूबा गिद्धौर का प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS CHATRA : चतरा जिले में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गिद्धौर प्रखंड के कटघरा रामनगर गांव में शुक्रवार को बाढ़ के कारण एक घर ढह गया, जिससे पति-पत्नी की मौत हो गई। इस घटना में दर्जनों मवेशी और बकरियां भी बह गईं। मृतकों की पहचान सत्येंद्र दांगी (45) और उनकी पत्नी रीना देवी (42) के रूप में हुई है, जो खेती-किसानी और बकरी पालन कर अपना जीवन यापन करते थे। उनका घर नदी के किनारे बना था। शुक्रवार सुबह हुई भारी बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई और पानी उनके घर में घुस गया। पानी के तेज बहाव के कारण उनका घर गिर गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी कई बकरियां भी बाढ़ के पानी में बह गईं। पुलिस ने सत्येंद्र दांगी का शव बरामद कर लिया है। इस प्राकृतिक आपदा में केवल इंसानी जान ही नहीं, बल्कि पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में गांव के बालेश्वर दांगी की दो गाय और एक बछड़ा, उपेंद्र दांगी के दो बैल, द्वारिका दांगी की एक गाय, रामलाल दांगी की दो गाय और एक बछड़ा, और लखन दांगी के मवेशी सहित कई लोगों की बकरियां नदी में बह गईं। इस घटना से ग्रामीणों में शोक का माहौल है और वे सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

इटखोरी में नदी उफान पर, घरों में घुसा पानी

पितीज गांव में दोतल्ला मकान भी डूबा, अधिकांश लोगों ने छत पर ले रखी है शरण

PHOTON NEWS CHATRA : इटखोरी थाना क्षेत्र में गुरुवार की मध्यरात से हो रही बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पितीज स्थित बसाने नदी उफान पर आ गई है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। निचले इलाकों में बने कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। पितीज पंचायत के राणा टोला सहित दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं।

ग्रामीण अपने परिवार और सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जूझ रहे हैं। पितीज गांव में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। यहां मुन्ना यादव का दो मंजिला मकान आधा पानी में डूब चुका है। परिवार के लोग छत पर शरण लिए हुए हैं और जरूरी सामान भी ऊपर पहुंचा दिया है। इसी तरह कई परिवारों को मजबूरी में ऊपरी मंजिल या छत पर शरण लेना पड़ा है।

बाढ़ के पानी में डूबा दो मंजिला घर ● फोटोन न्यूज

बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर ले जाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। नदी किनारे दर्जनों पेड़ बाढ़ के पानी में बह गए हैं। कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़कर गिर पड़े हैं, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। चतरा-इटखोरी मुख्य मार्ग पितीज के पास पानी में डूब गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोग दहशत में हैं और हर वक्त पानी बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार सुबह छह बजे धीरे-धीरे पानी बढ़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लिया। लोगों ने प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। हालांकि अब तक किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन घरों और सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। वहीं प्रशासनिक टीम के मौके पर न पहुंचने से लोगों में नाराजगी भी साफ झलक रही है।

BRIEF NEWS

एसिड से जलाकर छात्र की हत्या, घर से दूर मिला शव

BOKARO : बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में करीब 18 वर्षीय छात्र सूरज महतो की एसिड से जलाकर हत्या कर दी गई। उसका शव शुक्रवार शाम को उसके घर से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल से बरामद किया गया। शरीर पर जगह-जगह एसिड से जलने के निशान हैं। वह बुधवार शाम से लापता था। शुक्रवार शाम को जंगल में मवेशी चराने वालों की नजर पड़ी, तो इसकी सूचना गांव वालों को दी। इसके बाद शव की पहचान लापता सूरज महतो के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार देर शाम बेरमो डीएसपी बशिष्ठ नारायण सिंह, नावाडीह के थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी के साथ पेंक थाना की पुलिस भी पहुंची। फिलहाल हत्या के कारणों और हत्या करने वालों का कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस उसके परिजनों से पूछताछ करने के साथ छानबीन में जुटी है। पुलिस ने सूरज का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।

शोरूम में हुई चोरी का खुलासा, चार गिरफ्तार

KHUNTI : कर्रा थाना क्षेत्र के कुलहुटू स्थित ई-रिक्शा शोरूम में गत 14 अगस्त को हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र निवासी आशीष कुमार शर्मा (22), पुंदाग सेल सिटी रांची सुखदेव कुमार (29), रांची के रातू रोड निवासी सोनू कुमार वर्मा (30) और रांची के विद्यानगर रोड नंबर-3 ओझा कॉलोनी हरमू निवासी शुभम कुमार उर्फ विक्की (22) शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से लूट के कई सामान बरामद किए हैं। यह जानकारी तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने शुक्रवार को कर्रा थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मौके पर एसडीपीओ ने बताया कि जिले के पुलिस कप्तान मनीष टोप्पो को गुप्त सूचना मिली थी कि कुलहुटू टोटो शोरूम में चोरी किए गए सामानों को अपराधी रांची में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए तोरपा के एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर छापेमारी की गई और चारों ओरपितों को गिरफ्तार कर लिया। क्रिस्टोफर केरकेटटा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से टोटो की चार बैट्री, नौ हजार रुपये नकद, एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, एक ऑटो, एक कटर और तीन मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार सोनू कुमार वर्मा के खिलाफ पहले से ही डोरंडा थाना और कोतवाली थाने में एक-एक मामला दर्ज है। छापेमारी दल में एसडीपीओ के अलावा तोरपा के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, कर्रा के थाना प्रभारी मनीष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक जुगेश सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कांत कुमार, एसआइ मुकेश कुमार, एसआई भारत भूषण पटेल और शस्त्र बल के जवान शामिल थे।

धनबाद में चोरी की पांच बाइक के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ● फोटोन न्यूज

DHANBAD : पुलिस ने चोरी की पांच बाइक के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी तिसरा थाना क्षेत्र के कालीटांड़ फुटबॉल ग्राउंड के पास से हुई है। ये सभी अपराधी चोरी की बाइक बेचने का प्रयास कर रहे थे। मामले को लेकर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि धनबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुए बाइक को बरामद किया गया है। इस मामले में करकू भुइयां उर्फ करकू कुमार (24), सोनु भुइयां उम्र (20) और अरविंद कुमार साव उर्फ लड्डू (19) को गिरफ्तार किया गया। इस बाइक चोर गिरोह का संरगना सोनू सिन्हा फरार है।

इस गिरोह के खिलाफ तीसरा, झरिया और पुटकी थाना में भी प्राथमिकी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पुलिस ने पेश कर जेल भेज दिया गया।

अस्पताल में प्रसूता की मौत, लापरवाही के आरोप पर हंगामा, डॉक्टर-स्टाफ फरार

बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता की बिगड़ने लगी तबीयत, सुई देते ही मौत

PHOTON NEWS JAMTARA : जामताड़ा मेमोरियल अस्पताल में शुक्रवार को एक प्रसूता की मौत हो गई। वह पिछले तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक डॉक्टर को अस्पताल में ही बंधक बना लिया, जबकि अन्य डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि प्रसव के बाद से प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शुक्रवार को सुबह में जैसे ही डॉक्टर ने सुई लगाई, प्रसूता की मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह अस्पताल बिना किसी मान्यता के वर्षों से चल रहा है। यहां फजीर्वाड़ा कर इलाज किया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यह अस्पताल खुलेआम संचालित हो रहा था।

अस्पताल में मृतक के परिजन व अन्य ● फोटोन न्यूज

मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि मैं पीएचसी मधुपुर में पदस्थापित हूं, लेकिन यहीं 24 घंटे रहता हूं। इस बयान ने परिजनों और आम जनता के बीच आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब डॉक्टर की पदस्थापना किसी अन्य जगह है तो वह जामताड़ा में निजी अस्पताल में 24 घंटे कैसे मौजूद रहता है।

प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और सभी डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। इसी दौरान एक डॉक्टर को भीड़ ने अस्पताल के भीतर ही बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभालते हुए डॉक्टर को भीड़ से मुक्त कराया।

ग्रामीणों और परिजनों ने मांग की कि अस्पताल की मान्यता की पूरी जांच हो और दोषी डॉक्टरों एवं प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना के बाद से अस्पताल का पूरा स्टाफ फरार है।

किराना व्यवसायी के घर से नकद समेत 26 लाख की हो गई चोरी

PHOTON NEWS GIRIDIH : सरिया थाना क्षेत्र के पेठियाटांड़ में एक किराना व्यवसायी के घर गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने लगभग 16 लाख रुपये व 10 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। किराना व्यवसायी कैलाश मंडल ने बताया कि अन्य दिनों की भांति अपनी दुकान बंद कर ऊपर मकान में सोने चला गया। वहीं बगल के दो बंद कमरों से अज्ञात चोर दुकान के गोदाम में बने दरवाजे को तोड़कर घुसे। गोदरेज, अलमीरा बक्से आदि में रखे 16 लाख रुपये, सोने की 10 अंगूठी दो डायमंड रिंग समेत लगभग 26 लाख की संपत्ति चोरी हो गई। चोरी के वक्त परिवार के अन्य सदस्य घर के अगल-बगल के ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी।

चोरी का हाल बताते कारोबारी कैलाश मंडल

शायद चोरों ने नशे या नींद की दवा का स्प्रे किया हो। सुबह सभी लोग जब सोकर उठे तो घर के दरवाजे खुले व सामान बिखरा देखकर इसकी जानकारी हुई।

घटना की तत्काल सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची। वहीं दर्जनों लोग, विभिन्न पार्टी के नेता व सामाजिक कार्यकर्ता भी पीड़ित के घर पहुंचे। लोगों का कहना था कि लगभग एक माह पूर्व इसी गांव के पांच घरों में इसी प्रकार से चोरी हुई थी, लेकिन उन घटनाओं का आज तक खुलासा नहीं हुआ। चोरी की घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस की कार्यशैली के विरोध में सड़क जाम कर दिया।

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच को कल आएगी आयोग की टीम

GODDA : सूर्या हांसदा एनकाउंटर प्रकरण की जांच के लिए 24 अगस्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की (एनसीएसटी) की नौ सदस्यीय टीम आएगी। टीम ललमटिया के डकैता स्थित सूर्या हांसदा के पैतृक गांव जाएगी। टीम का नेतृत्व आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा और निरुपम चकमा करेंगी। एनसीएसटी के डिप्टी डायरेक्टर आरके दुबे ने गुरुवार को बताया कि टीम में आयोग के सदस्य सचिव वाईपी यादव, सलाहकार एचआर मीना, सुभाष रसिक सोरेन, राहुल यादव, अनुसंधानकर्ता राहुल कुमार सहित सदस्य के निजी सचिव कुशेश्वर साहू, रंजन चकमा आदि शामिल रहेंगे।

नई दिल्ली से आयोग की टीम देवघर हवाई अड्डा पर उतरेगी। वहां से गोड्डा सर्किट हाउस में विश्राम के बाद सूर्या हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत मामले की जांच करेगी। उसी दिन शाम को सर्किट हाउस में आयोग की टीम डीसी अंजली यादव और एसपी मुकेश कुमार के साथ बैठक कर जिला प्रशासन का पक्ष लेगी।

महिला के खाते में 62 लाख आने की बात गलत : बैंक

PALAMU : पलामू जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैदरनगर शाखा में महिला माया कुंवर के खाते में 62 लाख रुपये आने को बैंक ने अफवाह बताया है। बैंक ने इसे साइबर अपराधियों की चाल बताया है और ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

हैदरनगर के शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश ने बताया कि माया कुंवर के खाते में 62 लाख रुपये आने की बात पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु के साइबर थाने की तरफ से महिला के खाते पर 4910 रुपये का होल्ड लगाया गया है। यह होल्ड तब तक जारी रहेगा, जब तक साइबर अपराध का मामला सुलझ नहीं जाता।

ओमप्रकाश ने बताया कि साइबर सेल में माया देवी के खाते से पांच बार 982 रुपये के संदिग्ध लेन-देन की जांच चल रही है। हालांकि, महिला को 4910 रुपये को छोड़कर अपने खाते से बाकी राशि का लेन-देन करने की अनुमति है।

शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बैंक कभी भी ग्राहकों से ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगता है।

साइबर अपराधी अक्सर तरह-तरह के प्रलोभन देकर ग्राहकों को अनावश्यक एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, जिसके झांसे में आने से खाता खाली हो सकता है। बैंक ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी ग्राहक को एप्लिकेशन डाउनलोड करने का मैसेज नहीं भेजते हैं।

पहल क्रमवार 25-25 सामान्य कैदियों को किया जाएगा स्थानांतरित

मेदिनीनगर से 200 कैदी जाएंगे हजारीबाग जेल

- मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में बंद हैं नक्सलियों सहित जमशेदपुर व धनबाद के भी अपराधी

PHOTON NEWS PALAMU : मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में क्षमता से अधिक कैदी बंद होने के कारण प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 200 कैदियों को जेपी केंद्रीय कारा, हजारीबाग ट्रांसफर किया जाएगा। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी और हर चरण में लगभग 25 कैदियों को शिफ्ट किया जाएगा। ट्रांसफर के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मेदिनीनगर केंद्रीय कारा की क्षमता 760 कैदियों की है, जबकि यहां 925 कैदी बंद हैं। इनमें 300 से अधिक सजायाफ्ता कैदी और फांसी की सजा पाए तीन कैदी भी शामिल हैं। क्षमता से करीब 200 कैदी अधिक होने की वजह से जेल पर दबाव बढ़ा है। मेदिनीनगर केंद्रीय कारा इन दिनों पूरे झारखंड में चर्चा का केंद्र है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप महीनों से यहीं बंद है। हाल ही में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को यहां ट्रांसफर किया गया। गैंगस्टर डबलू सिंह आत्मसमर्पण के बाद इसी जेल में है। इसके अलावा कोयलांचल और जमशेदपुर के कई हाई-प्रोफाइल कैदी भी यहीं हैं। इतने बड़े अपराधियों की मौजूदगी ने इस जेल को झारखंड को अतिसंवेदनशील जेलों में ला खड़ा किया है।

फाइल फोटो

सुरक्षा को लेकर सतर्कता

मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में पहले से ही नक्सल संगठन से जुड़े कई बड़े कैदी बंद हैं। ऐसे में सुरक्षा पर प्रशासन और सतर्क है। इसी वजह से आईजी और डीआईजी स्तर से डीसी और एसपी को विशेष पत्र लिखकर सुरक्षा के लिए कई निर्देश दिए गए हैं।

> कारा महानिरीक्षक के निर्देश पर 200 कैदियों को जेपी केंद्रीय कारा हजारीबाग भेजा जाएगा। ट्रांसफर कई चरणों में होगा। हर चरण में करीब 25 कैदियों को भेजा जाएगा। इसमें केवल सामान्य कैदी होंगे, कोई हाई प्रोफाइल या हार्डकोर कैदी शामिल नहीं रहेगा।
> – भगीरथ करजी
> जेल अधीक्षक
> मेदिनीनगर केंद्रीय कारा

दारोगा पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी

JAMTARA : फतेहपुर थाना में पदस्थापित एएसआई विरंची भोक्ता पर एक महिला ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आरोपी एएसआई ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा मारपीट कर जबरन दुराचार किया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष जामताड़ा में बयान के लिए प्रस्तुत किया। वहां भी पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आमजन के बीच चर्चा जोरों पर है कि जिस पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, यदि वही कानून की सीमा लांघ दे तो आम जनता किस पर भरोसा करे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाली है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम लोगों का विश्वास पुलिस पर कायम रह सके। वहीं कुछ लोग इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।

लातेहार में यात्री बस व बाइक में टक्कर, दो की हो गई मौत

मनिका थाना क्षेत्र के देवबार मोड़ के पास हुई दुर्घटना

PHOTON NEWS LATEHAR : जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत देवबार मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर शुक्रवार को यात्री बस और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। इसमें एक मृतक की जब से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उसकी पहचान अब्दुल हसीम सरवर (40) के रूप में की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस धारक उत्तर प्रदेश नोएडा का है। जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार लातेहार की ओर से मनिका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मोड़ के पास सामने से आ रही यात्री बस से मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है, जिस कारण यहां अक्सर दुर्घटना हो रही है। लोगों ने सड़क मरम्मत करने की मांग जिला प्रशासन और सरकार से की है।

घटनास्थल पर बस में फंसी बाइक ● फोटोन न्यूज

BRIEF NEWS

प्रदेश भाजपा की जांच टीम ने बाबूलाल मरांडी को सौंपी रिपोर्ट

RANCHI : सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से गठित सात सदस्यीय जांच टीम ने जांच पूरी कर ली है। शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में जांच टीम के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर जांच टीम के सदस्यों में शामिल पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, भानू प्रताप शाही, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल उपस्थित शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर के बाद बाबूलाल मरांडी ने जांच टीम का गठन किया था। टीम ने गोड्?डा जाकर हांसदा के परिजनों से मिलकर जानकारी ली और प्रदेश को अध्यक्ष को आज रिपोर्ट सौंप दी।

कांके के पूर्व अंचल अधिकारी जयकुमार राम का निधन

KANKE : शुक्रवार को कांके के पूर्व अंचल अधिकारी जय कुमार राम का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उनका तबादला कांके अंचल से पलामू जिले के पांकी अंचल में किया गया था। जय कुमार राम का नाम कांके में तैनाती के दौरान कई विवादों से जुड़ा रहा। वे भूमि घोटाले के आरोपी रहे थे और प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया था। हालांकि इस मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य कारणों से वे पिछले कुछ समय से सक्रिय प्रशासनिक कार्यों में भी ज्यादा शामिल नहीं हो पा रहे थे। उनके निधन पर कांके विधायक सुरेश बैठा, प्रखंड प्रमुख सोमनाथ मुंडा, उप प्रमुख अंजय बैठा, कांके सीओ अमित भगत, बीडीओ विजय कुमार, सीआई चितरंजन टूटू, कांग्रेस नेता जमील अख्तर, संजर खान, जावेद अख्तर ने शोक व्यक्त किया।

झारखंड की नदियों की सफाई और शहरों को हरा-भरा रखने पर हुई चर्चा

RANCHI : राज्य के पांच शहरों से गुजरनेवाली नदियों के प्रबंधन, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर 20 अगस्त से शुरू हुए तीन दिनों तक आयोजित कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। रांची के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में रांची, आदित्यपुर, धनबाद, चास और साहिबगंज एवं राजमहल नगर निकाय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नदियों के प्रबंधन में किन किन बातों पर ध्यान रखकर कार्यक्रम और योजना तैयार करना है। इसकी जानकारी दी गई। इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की संस्था राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली नें एक कंपनी (एलुवियम) का चयन किया है जो नगर निकायों के साथ मिलकर योजना चिन्हित करेगी और आगे इसपर कार्य किया जाएगा।

आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को जेल से किया जाएगा रिहा

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक हुई। इसमें राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ-साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। मीटिंग में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई हेतु अनुशंसित एक-एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने रिहाई के लिए अनुशंसित कैदियों की उम्र एवं पारिवारिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति की भी पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर गहन विचार के बाद 51 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी।

- सीएम की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में बनी सहमति
- रिहाई संबंधी 37 नए और पिछली बैठक के अस्वीकृत मामलों की भी हुई समीक्षा

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य • फोटोन न्यूज

नया जीवन शुरू करने के लिए करें प्रेरित

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में समीक्षा के उपरांत राज्य के विभिन्न कारागारों में 14 वर्ष या उससे अधिक समय से सजा काट रहे वैसे कैदी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है तथा जेल में उनका आचरण अच्छा है, उन्हें रिहा किया जाता है। ऐसे में रिहा हो रहे कैदियों को एक बेहतर सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि रिहाई से संबंधित अनुशंसित मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें कैदियों के बीमार होने तथा कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात कही गई है।

470 कैदियों को मिल रहा योजनाओं का लाभ

अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सहमति के बाद वर्ष 2019 से अब तक राज्य के विभिन्न कारागारों से 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। इनमें 558 कैदियों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया गया है। 61 बंदियों का भौतिक सत्यापन किया जाना बाकी है। यह भी बताया गया कि वर्ष 2019 से अब तक रिहा हुए 619 में से 470 कैदियों को सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा ई- श्रम कार्ड इत्यादि योजनाओं के लाभ से जोड़ा गया है।

10 दिनों का मिला अल्टीमेटम, जमा नहीं करने पर होगी कुर्की-जब्ती

रांची नगर निगम ने जारी की 500 टैक्स बकाएदारों की लिस्ट

PHOTON NEWS RANCHI : रांची नगर निगम ने कर न चुकाने वाले शीर्ष 500 बड़े बकाएदारों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। यह कदम टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता लाने और समय पर टैक्स पेमेंट सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। निगम द्वारा जारी आम सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन लोगों के नाम इस सूची में हैं, उन्हें इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपने-अपने बकाया कर की पूरी राशि जमा करनी होगी। निगम ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित बकायेदारों के विरुद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 184 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत निगम बकाया वसूली के लिए संपत्ति कुर्की, जब्ती और अन्य कठोर कदम उठा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, इन शीर्ष 500 बकाएदारों पर करोड़ों रुपये तक का टैक्स बकाया है, जो लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया है। नगर निगम ने यह सूची सार्वजनिक कर बकायेदारों पर दबाव बनाने और आम जनता को जागरूक करने की दिशा में यह रणनीति अपनाई है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सूचना अंतिम चेतावनी के रूप में दी जा रही है। इसके बाद किसी भी प्रकार की रियायत या छूट की संभावना नहीं रहेगी। करदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने दायित्वों का निर्वहन करें और कानूनी कार्रवाई से बचें।

- बार-बार डिमांड नोट के बावजूद बकाया टैक्स नहीं जमा करा रहे हाउस होल्डर
- समय पर टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम

नागरिकों से सहयोग की अपील

निगम अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि शहर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। टैक्स से प्राप्त राशि का उपयोग स्वच्छता, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास में किया जाता है।

शहर के बड़े होल्डिंग टैक्स बकाएदार

- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी, सर्कुलर रोड, रांची)- 16,54,297.88
- सरस्वती शिशु विद्या मंदिर (धुर्वा, रांची) - 14,89,550.56
- इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट (पुंदाग, रांची) -12,05,799.96
- हर्ष मुंजाल (फिरायालाल पब्लिक स्कूल कैंपस, मेन रोड, रांची) - 11,23,549.72
- डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी (डीएवी पब्लिक स्कूल, बरियातू, बूटी रोड, रांची) - 10,79,238.66
- गोविंद प्रसाद भला, रामअवतार भला (हिंदुस्तान बिल्डिंग, मेन रोड, रांची) - 10,34,460.04
- सुशील लोहिया (कचहरी रोड, रांची) - 10,33,414.24
- इला रानी, कमल कुमार सिंह, प्रकाश यादव (कोकर, एच.बी. रोड, रांची) - 9,84,992.52
- अनिल कुमार गुप्ता व अन्य (हरमू रोड, रांची) - 8,95,256.76
- सुषमा देवी (दत्ता विला, मोरहाबादी, रांची) - 7,56,778.76
- छोटानागपुर पब्लिक स्कूल (बूटी रोड, गाड़ी, रांची) - 7,48,408.60
- डॉ. सच्चिदानंद प्रसाद (रिम्स चौक, बरियातू, रांची) - 7,31,602.04
- नजरत हुसैन व अन्य (मेहंदी बागान, खूंटी रोड, रांची) - 6,69,222.12
- कवलजीत सिंह सेठी (सेठी कॉर्पोरेट, मेन रोड, रांची) - 6,64,707.44
- अर्ति आनंद, आशिता आनंद, संजय आनंद (अर्जन पैलेस, मेन रोड, रांची) - 6,64,696.18

फुलवंती देवी (प्रगति एन्क्लेव, नई अलकापुरी, रांची) - 6,57,184.68

मंजुला देवी (हेसाग, रांची) - 6,35,000.84

निर्जन राम, सहदेव राम (अरगोड़ा बायपास चौक, रांची) - 6,15,160.80

क्वालिटी इन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (होटल क्वालिटी इन, स्टेशन रोड, रांची) - 5,69,493.40

रिम्स की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाएगी जीबी की बैठक

RANCHI : शुक्रवार को रिम्स की अव्यवस्थाओं को लेकर दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें संस्थान में फैली अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही को पर हाईकोर्ट ने सख्ती की। कोर्ट ने रिटायर्ड जज की निगरानी में जीबी की बैठक कराने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह केवल कानूनी प्रावधानों पर नहीं, बल्कि रिम्स की वास्तविक स्थिति पर भी विचार करेगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने एफेडेविट दाखिल कर बताया कि रिम्स निदेशक के पास सभी प्रशासनिक शक्तियां होती हैं और वे संस्थान के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि रिम्स की समस्याओं की बड़ी वजह गवर्निंग बॉडी की नियमित बैठक नहीं होना है। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए 8 से 14 सितंबर के बीच जीबी की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यह बैठक एक रिटायर्ड जज की निगरानी में हो, जो बतौर ऑब्जर्वर पूरे प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने 13 अगस्त को रिम्स निरीक्षण की रिपोर्ट और उससे संबंधित तस्वीरें सभी जीबी सदस्यों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया है, ताकि वे जमीनी हालात को ठीक से समझ सकें।

- 8 से 14 सितंबर के बीच जीबी की बैठक कराने का कोर्ट ने दिया आदेश
- हॉस्पिटल की अव्यवस्था को लेकर पीआईएल पर हुई सुनवाई

हॉस्पिटल की ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि क्या हॉस्पिटल का ऑडिट होता है। इस पर एजी ने बताया कि इसका ऑडिट होता है। कोर्ट ने ऑडिट की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई में देने को कहा। कोर्ट ने रिम्स निदेशक को आदेश दिया कि वे संस्थान में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही नियुक्तियों और मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी के बारे में विस्तृत जानकारी ऑब्जर्वर के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी।

टेबल पर शव रखकर हंगामा करने वाले दो नामजद और 150 अज्ञातों पर केस

PHOTON NEWS RANCHI : हिंदपीढ़ी थाना के टेबल पर मो रिजवान का शव रखकर हंगामा करने के मामले में दो नामजद सहित 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। केस में नामजद आरोपी मो शाबिर और भोलू उर्फ बाबा मुश्ताक को बनाया गया है। यह केस हिंदपीढ़ी थाना के एएसआइ चुन्नू किस्कू की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस पदाधिकारी के अनुसार, 20 अगस्त को मो रिजवान का शव छोटा तालाब से निकाला गया था। आरोपी पक्ष के लोग मो रिजवान को खोज निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग कर रहे थे। एनडीआरएफ की टीम के आने में विलंब होने पर आरोपियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था। दिन के करीब एक बजे तालाब से मो रिजवान का शव निकाला गया। इसके बाद वे शव को साथ लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिंदपीढ़ी थाना पहुंचे गये। थाना पहुंचने के बाद उन्होंने शव को थाना के टेबल पर रख दिया और पुलिस के साथ गाली-गलौज करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस वजह से थाना का काम बाधित हो गया। कई प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया, फिर समझा बुझा कर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया गया। दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात लोगों की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

कथित वोट चोरी के खिलाफ 26 को विधानसभा में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

PHOTON NEWS RANCHI : कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को परिसदन कचहरी में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लोकतंत्र की रक्षा करना और संविधान की ओर से दिए गए हर नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा करना, देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि का धर्म है। बैठक में प्रदीप यादव ने कहा कि संविधान से हमें मतदान का अधिकार प्राप्त है। वोट की हेराफेरी और चोरी सीधे-सीधे संविधान का उल्लंघन है। इस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 अगस्त को इंडिया गठबंधन इसे लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार विरोध-प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार इसके विरोध में प्रस्ताव लाएगी केंद्र सरकार को सशक्त संदेश देगी। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा की रक्षा का आंदोलन है।

बैठक करते प्रदीप यादव व अन्य कांग्रेस के नेता • फोटोन न्यूज

चाय पीने के बाद पीजी डॉक्टर की बिगड़ी तबीयत, कैंटीन को किया गया सील

PHOTON NEWS RANCHI : रिम्स में ड्यूटी के दौरान गायनेकोलॉजी विभाग में तैनात एक महिला पीजी डॉक्टर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, ड्यूटी के दौरान विभाग के कई डॉक्टरों ने कैंटीन से चाय मंगाई थी। चाय पीने के बाद डॉक्टर ने अपने साथियों से चाय का टेस्ट खराब होने की शिकायत की। इसके बाद उनके साथियों ने चाय नहीं पी। कुछ ही देर में पीजी डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टर को आईसीयू में 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी हैं। वहीं कैंपस में चल रहे दोनों कैंटीन को सील कर दिया है। इस घटना ने रिम्स कैंपस में हड़कंप मचा दिया है। कैंटीन की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। अब घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ में चिंता का माहौल है। यह मामला पॉइजनिंग से संबंधित प्रतीत हो रहा है घटना की गंभीरता को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने जांच हेतु मेडिसिन एचओडी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है।

- रिम्स में ड्यूटी के दौरान कई डॉक्टरों ने दिया था चाय का ऑर्डर
- कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की टीम ने भी किया था कैंटीन का इंस्पेक्शन
- बिना टेंडर के अवैध रूप से कैंटीन संचालन की बात आई थी सामने

कार्यक्रम झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि ओडिशा के राज्यसभा सांसद ने कहा-

सीएसआर फंड के सही इस्तेमाल से आ सकता है बड़ा बदलाव : सुजीत

PHOTON NEWS RANCHI : ओडिशा के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि समाज के उत्थान में कॉरपोरेट वर्ल्ड का भी बड़ा योगदान है। कॉरपोरेट कंपनियां धन और रोजगार दोनों का निर्माण करती हैं। इन कंपनियों के सीएसआर फंड के सही इस्तेमाल से समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। कॉरपोरेट कंपनियां अगर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समवन्य बनाकर अपने सीएसआर फंड का सही इस्तेमाल करें, तो इसका लाभ अपेक्षित लोगों तक पहुंच सकता है। इससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। इसलिए सभी कॉरपोरेट कंपनियां सीएसआर फंड का सही उपयोग करें। ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सुजीत कुमार शुक्रवार को स्थानीय होटल में आयोजित दो दिवसीय झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कॉन्क्लेव का आयोजन मिशन ब्लू फाउंडेशन, आईडिएट इंस्पायर इग्नाइट (आई-3) फाउंडेशन और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का थीम सीएसआर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ : ब्रिजिंग इंपैक्ट एंड इनोवेशन है।

कार्यक्रम में भाग लेते ओडिशा के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार व अन्य • फोटोन न्यूज

लोकल प्रोडक्ट को भी प्रमोट करें कॉरपोरेट कंपनियां

राज्यसभा सांसद ने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियां लोकल प्रोडक्ट को भी प्रमोट करें। लोकल फॉर वोकल के तहत बने प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा, तो इसका फायदा स्थानीय लोगों को होगा। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड में सीएसआर फंड का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार के दबाव में कंपनियां सीएसआर फंड के तहत काम कर रही हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। कंपनियों से आग्रह है कि नियम के तहत सीएसआर फंड का इस्तेमाल करें।

स्वर्णिम भारत एक्सपो में दूसरे दिन उद्यमिता व संवाद का हुआ संगम

PHOTON NEWS RANCHI : परिचित फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वर्णिम भारत एक्सपो का दूसरा दिन नवाचार, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास के विचारों से ओतप्रोत रहा। सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद दीपक प्रकाश और डॉ. रविंद्र राय जैसे गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और युवाओं के प्रयासों की सराहना की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह एक्सपो युवाओं को तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करता है। दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण रहा विकसित भारत 2047 नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता विषय पर पैनल चर्चा, जिसमें वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। साथ ही, छात्रों की भारी भागीदारी ने आयोजन को और बेहतर बना दिया। सीएसआईआर, इसरो, एनएचपीसी, आईसीएमआर, आईसीएआर, बीआईएस सहित कई राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी रही।

अंजुमन इस्लामिया का चुनाव बायलॉज के अनुरूप होगा : कमर सिद्दीकी

RANCHI : अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव संयोजक कमर सिद्दीकी ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया रांची का चुनाव बायलॉज के अनुरूप होगा। साफ-सुथरा चुनाव कराना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में फर्जी वोटर रोकना और स्थल निरीक्षण कर मतदाता सूची तैयारकी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता बनाने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इससे पूर्व सभी क्षेत्रों में चुनाव को लेकर पोस्टर से प्रचार-प्रसार कर मतदाता को जागरूक किया जाएगा।

समाचार सार

रेडक्रॉस के प्रदेश चेयरमैन बने विजय सिंह

JAMSHEDPUR : रेडक्रॉस, पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय सिंह को रेडक्रॉस का प्रदेश चेयरमैन बनाया गया है। उन्हें यह पद राज्यपाल सह रेडक्रॉस की झारखंड राज्यशाखा के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार के अनुमोदन से प्राप्त हुआ। इसके अलावा हजारीबाग जिला रेडक्रॉस शाखा के सचिव तनवीर सिंह को उपसभापति (वाइस चेयरमैन) बनाया गया है।

विस में दी गई श्याम सुंदर महतो को श्रद्धांजलि

CHAIBASA : विधानसभा के मानसून पूरक सत्र में शिक्षाविद् श्याम सुंदर महतो के प्रति शोक-संवेदना व्यक्त की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक-संवेदना का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा दिवंगत श्याम सुंदर महतो सहित अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई। श्याम सुंदर महतो कोल्हान क्षेत्र के महान शिक्षाविद् और समाजसेवी थे, जिन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके कार्यों को लेकर चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य सुखराम उरांव ने विधानसभा अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण कराया था।

धरमबहाल में याद किए गए गुरुजी व रामदास

GHATSILA : धरमबहाल पंचायत के लालड़ीह स्थित माटीकला भवन में शुक्रवार को झामुमो धरमबहाल पंचायत कमेटी की ओर से दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि जगदीश भकत, पूर्व केंद्रीय सदस्य कान्हु सामंत, बाबूलाल मुर्मू, मो. जलील, पंचायत अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सचिव राजा सिंह सहित कई झामुमो कार्यकर्ता व स्थानीय निवासी उपस्थित थे।

गोविंदपुर में दिखेगी गणेश की थ्री-डी एनिमेटेड प्रतिमा

JAMSHEDPUR : छोटा गोविंदपुर के पुतुल मैदान में शुक्रवार को श्रीश्री गणेश पूजा समिति न्यू स्टूडेंट ब्वॉयज क्लब द्वारा गणेश पूजा का भूमिपूजन किया गया। समिति के अध्यक्ष सुजल कुमार ने बताया कि इस वर्ष पूजा पंडाल काल्पनिक थीम पर बनाया जा रहा है। यहां पहली बार भक्तों को थ्री-डी एनिमेटेड गणेश प्रतिमा का दर्शन होगा, जो इस बार का विशेष आकर्षण होगा। पूजा चार दिनों तक चलेगी, जिसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। समिति ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों और युवाओं के लिए विशेष खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और उत्सवमय बनेगा। भूमिपूजन के मौके पर समिति के सदस्य हेमंत, आशीष, गुड्डू, विवेक, सनी, अमन, सोनू, गौरव, साहिल, अनिमेष, तापस, श्याम, नीरज, जयशंकर, सौरभ, कृष्णा, संजू, आकाश, अंजन, सचिन, करण, अभिषेक, मनीष, सनी, साहिल और देवानंद मौजूद रहे।

सीमेंट प्लांट के कर्मियों को ₹ 2,37,625 तक बोनस

JAMSHEDPUR : जोजोबेड़ा स्थित नुवोको सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का सलाना बोनस समझौता शुक्रवार को हो गया। समझौते के मुताबिक कर्मचारियों को न्यूनतम 63,111 रुपये एवं अधिकतम 2,37,625 रुपये मिलेगा। बोनस राशि का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ मिलेगा। समझौता-पत्र पर प्रबंधन की ओर से प्लांट हेड हरि किशोर गरिकापति, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (एचआर) अर्नब बासु, जीएम (एचआर) राजीव मिश्रा, डीजीएम (एकाउंट्स) अभिजीत मंडल, आलोक वाजपेयी एवं समीर कुमार तथा यूनियन से अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, डिप्टी प्रेसिडेंट विनय त्रिवेदी, वाइस प्रेसिडेंट संजीव श्रीवास्तव, महामंत्री बिजय खां, सहायक सचिव सुनील शुक्ला, कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, कमेटी मेंबर विजय देव, एनबी थापा व रणवीर कर्मकार ने हस्ताक्षर किए।

सोना देवी विश्वविद्यालय का हुआ इंडक्शन प्रोग्राम

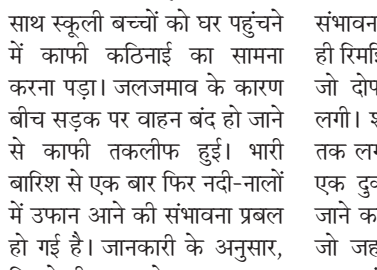

GHATSILA : सोना देवी विश्वविद्यालय का इंडक्शन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अभिजीत ए ननोटी, प्रबंध निदेशक, जेसीएपीसीपीएल जमशेदपुर, सोना देवी विश्वविद्यालय के संस्थापक सह कुलाधिपति प्रभाकर सिंह, कुलपति डॉ. जेपी मिश्रा, कुलसचिव डॉ. गुलाब सिंह आजाद तथा सोना देवी मेमोरियल एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट की सदस्य डॉ. निर्मला शुक्ला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'बढ़ते कदम-2025' का विमोचन भी किया गया। पत्रिका को डॉ. नीलमणि कुमार तथा उनके संपादकीय सहयोगियों ने तैयार किया है।

बागबेड़ा में बहू से विवाद के बाद वृद्धा ने कर लिया आत्मदाह, मौत

घटना के वक्त घर में मौजूद थे बेटा-बहू

● पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस

फाइल फोटो

PHOTON NEWS JSR : बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित हरहरगुट्टू में शुक्रवार दोपहर एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां बहू से हुए विवाद के बाद एक 70 वर्षीय महिला ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। दोपहर करीब 2 बजे हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला के घर से अचानक चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। शोर सुनकर पड़ोसी जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वृद्धा आग की लपटों में घिरी हुई थीं। जब तक लोग कुछ समझ पाते और मदद के लिए आगे आते, तब तक महिला पूरी तरह से जल चुकी थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद भी परिवार के किसी सदस्य ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के समय घर में महिला का बेटा और बहू दोनों मौजूद थे। इस लापरवाही को लेकर आसपास के लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं ताकि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

टेल्को में फंदे पर लटका मिला ऑटो चालक का शव

JAMSHEDPUR : टेल्को थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम 34 वर्षीय ऑटो चालक जय सिंह ने आत्महत्या कर ली। मंडल बस्ती निवासी जय सिंह को गंभीर हालत में उसके घर में फंदे पर लटकता पाया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना टेल्को पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जय सिंह को फंदे से उतारकर तत्काल इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया। हालांकि, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पंचनामा तैयार करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के मुताबिक, जय सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ रिश्ते को लेकर परेशान था। परिजनों ने बताया कि पहले वह काफी मिलनसार था, लेकिन हाल के दिनों में उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वह अक्सर चुपचाप रहने लगा था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था।

टेल्को थाना प्रभारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।

मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज के छात्र ने खाया जहर, मौत

मृतक की फाइल फोटो

JAMSHEDPUR : बारीडीह स्थित मणिपाल-टाटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र दिव्यांशु पांडेय ने गुरुवार की रात आत्महत्या कर ली। इस घटना से कॉलेज में शोक का माहौल है। वह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का निवासी था। जानकारी के अनुसार, दिव्यांशु ने गुरुवार शाम अपने हॉस्टल के कमरे में सल्फास की गोलियां खा ली थी। जानकारी मिलते ही कैंपस में उपस्थित छात्रों ने एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन करीब 40 मिनट तक इंतजार के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची। तब गंभीर हालत में उसे किसी अन्य वाहन से एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से टीएमएच रेफर किया गया। छात्रों का आरोप है कि समय रहते समुचित उपचार नहीं होने के कारण दिव्यांशु ने टीएमएच में इलाज के दौरान देर रात करीब 1.30 बजे दम तोड़ दिया। छात्रों के आरोपों के विपरीत, कॉलेज प्रबंधन की ओर से प्रवक्ता प्रियंका सिंघल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही दिव्यांशु को कॉलेज की एंबुलेंस से तत्काल टीएमएच ले जाया गया, जहां उन्हें शाम 7 बजे भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया है कि कॉलेज परिसर में हमेशा दो एंबुलेंस उपलब्ध रहती है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद भाई शुभ्रांशु पांडेय को शव सौंप दिया।

नेशनल पावर लिफ्टिंग व बेंचप्रेस में ओडिशा व छत्तीसगढ़ का जलवा

विजेता प्रतिभागियों के साथ अतिथि व आयोजक ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS JSR : इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय सीनियर महिला व पुरुष नेशनल पावर लिफ्टिंग एवं बेंचप्रेस चैंपियनशिप-2025 का आयोजन बिष्टुपुर स्थित मिलानी में हुआ। इसमें 17 राज्यों से लगभग 310 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुषों के 9 और महिलाओं के 8 ग्रुप में मुकाबले हुए। ओवरऑल पावर लिफ्टिंग (इक्विप्ड) : विजेता : छत्तीसगढ़, प्रथम उपविजेता : उत्तर प्रदेश, द्वितीय उपविजेता : आंध्रप्रदेश। ओवरऑल पावर लिफ्टिंग (अनइक्विप्ड) : विजेता : ओडिशा, प्रथम उपविजेता : छत्तीसगढ़, द्वितीय उपविजेता : असम. नेशनल बेंचप्रेस (पुरुष वर्ग) : विजेता : मणिपुर, प्रथम उपविजेता : ओडिशा, द्वितीय उपविजेता : उत्तर प्रदेश। नेशनल बेंचप्रेस (महिला वर्ग) : विजेताः ओडिशा, प्रथम उपविजेता : उत्तर प्रदेश, द्वितीय उपविजेता : आंध्रप्रदेश। सीनियर स्ट्रांग के व्यक्तिगत विजेता : पुरुष (इक्विप्ड) : राजेंद्र पाटिल (झारखंड), महिला (इक्विप्ड) : अंजना सिंह (छत्तीसगढ़), पुरुष (अनइक्विप्ड) : दिलीप पटेल (छत्तीसगढ़), महिला (अनइक्विप्ड) : बनानी बिस्वास (ओडिशा). प्रतियोगिता में सभी बर्गों के बिजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के डायरेक्टर अरिजीत सरकार, फेडरेशन के महासचिव कौस्तव दत्ता, संयुक्त सचिव राहुल शुक्ला व संपा गुहा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। महासचिव कौस्तव दत्ता ने बताया कि चैंपियनशिप में देश के प्रमुख पावर लिफ्टर्स ने भाग लिया।

कदमा में 50 बेड का अस्पताल बनाने का दिया गया प्रस्ताव

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉ. साहिर पॉल शुक्रवार को उलियान स्थित शहीद निर्मल सेवा सदन आए थे। उन्होंने यहां अटल मोहल्ला क्लीनिक व मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक के लिए एमओयू किया। इस अवसर पर शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति,उलियान के महासचिव श्री.लालटू महतो ने उनके समक्ष कदमा में 50 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि जगह उपलब्ध कराने की स्थिति में हम अस्पताल खोलने के लिए तैयार हैं। लालटू महतो ने कहा कि हमलोग एक सप्ताह में सिविल सर्जन कार्यालय को जमीन उपलब्ध करा देंगे। इस अवसर पर शहीद निर्मल सेवा सदन, शास्त्रीनगर के महासचिव गौतम कुमार बोस, राजकुमार दास, निमाई गोप व शिवराज सिंह भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री का सचिव बनकर किसानों से ठगी की कोशिश

गव्य विकास पदाधिकारी राज नारायण सारस्वत

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में साइबर अपराधियों द्वारा झारखंड सरकार की योजनाओं के नाम पर गव्य किसानों को फर्जी फोन कर ठगने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में जिला गव्य विकास विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना चाईबासा में मामला दर्ज कराया है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी राज नारायण सारस्वत ने बताया कि साइबर अपराधियों ने स्वयं को झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का सचिव मनोरंजन कुमार बताकर गव्य किसानों को फोन किया। उन्होंने कहा कि किसानों की योजना स्वीकृत हो गई है, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए पहले भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने पर योजना से नाम काटने की धमकी भी दी गई। जिला गव्य विकास पदाधिकारी ने साइबर अपराधियों के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से फर्जी और साइबर ठगी का मामला है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक व सदर डीएसपी को भी दी गई है। जिला गव्य विकास विभाग ने बताया कि जिले में मंगलवार के कुछ गव्य किसानों को मोबाइल नंबर 7063219301 और वाट्सएप नंबर 9038197598 से कॉल कर ठगों ने स्वयं को झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का सचिव मनोरंजन कुमार बताया।

एनएमएल के आविष्कारों से अवगत हुए स्कूली छात्र

प्रयोगशाला में छात्रों को जानकारी देते एनएमएल के वैज्ञानिक ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : बर्मामाइंस स्थित सीएसआईआर-एनएमएल में शुक्रवार को श्रीनाथ पब्लिक स्कूल के 54 छात्र-छात्राओं का दल पहुंचा, जहां वे एनएमएल (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला) के अविष्कारों से अवगत हुए। सीएसआईआर-जिज्ञासा वर्चुअल प्रयोगशाला परियोजना के अंतर्गत हुए इस कार्यक्रम में एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने छात्रों और शिक्षकों का स्वागत करते हुए सीएसआईआर-एनएमएल की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, तकनीकी विकास और अनुसंधान में योगदान की जानकारी दी। डॉ. सर्मिष्ठा सागर (मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, आईएमडीसी) ने सीएसआईआर-एनएमएल की भूमिका और इसके अनुसंधान एवं विकास कार्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके बाद डॉ. अनिमेष जाना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईएमडीसी ने जिज्ञासा कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की। छात्रों ने कई अनुसंधान प्रयोगशालाओं का भ्रमण किया, जिनमें अप्लाइड एवं एनालिटिकल केमिस्ट्री डिवीजन, क्रीप परीक्षण सुविधा, धातुओं की नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ई-वेस्ट रीसायक्लिंग, पीतल गलाने की प्रक्रिया तथा डू इट योरसेल्फ किट का प्रदर्शन शामिल था।

खैनी बेचने वाले तीन दुकानदारों पर लगा 1800 रुपये का जुर्माना

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड में आसनतलिया से प्रखंड कार्यालय तक शुक्रवार को जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण के मुक्ति बिरुवा, बीडीओ कांचन मुखर्जी तथा पुलिस ने खैनी बेचने वाले दुकानों पर छापामारी की गई। छापेमारी के दौरान तीन दुकानों में खैनी बेचने पर लगभग 1800 रुपये जुमार्ना लगाया गया। इस संबंध में चक्रधरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी कांचन मुखर्जी ने बताया कि चक्रधरपुर को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। इसलिए यहां तंबाकू-खैनी बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी तंबाकू का विज्ञापन देखा जाएगा, उसे जब्त किया जाएगा। चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में कई जगहों पर गुटखा का बैनर लगाया गया है, जो गैरकानूनी है।

करंट प्रवाहित तार की चपेट में आकर 6 बकरियों की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

पश्चिमी सिंहभूम के गुवा थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना, मुआवजे की मांग

घटनास्थल पर मृत पड़ी बकरियां ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना अंतर्गत तितलीघाट गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। गांव की ग्वाला टोली स्थित बिजली के खंभे पर हुए वज्रपात से करंट प्रवाहित तार टूटकर जमीन पर गिर गया। इसकी चपेट में आने से तीन ग्रामीणों की 6 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीण मुंडा मनचुडिया सिद्धू ने बताया कि बिजली के खंभे पर वज्रपात होते ही तेज आवाज के साथ तार टूट गया। जमीन पर गिरते ही आसपास चर रही बकरियां उसकी चपेट में आ गई। इसमें बामिया चांपिया की 3, मोसो चांपिया की 2 और कैरा चांपिया की 1 बकरी की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि वहां कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही और जर्जर तारों की वजह से अक्सर खतरा बना रहता है। अगर समय रहते मरम्मत और निगरानी की जाती, तो यह घटना टल सकती थी।

पीड़ित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग से तुरंत मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि गरीब परिवारों की आजीविका इन बकरियों पर निर्भर थीं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से मांग की है कि वे जल्द से जल्द जर्जर तारों की मरम्मत करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए।

आफत की बारिश सड़क से घर तक घुसा पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त

पांच घंटे लगातार हुई मूसलाधार वर्षा से घाटशिला जलमग्न

PHOTON NEWS GHATSILA : क्षेत्र में पांच घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से घाटशिला अनुमंडल का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण सड़क से घर तक चहुंओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जलजमाव की स्थिति ऐसी हो गई है कि घाटशिला मुख्य सड़क पर दो से तीन फीट तक पानी जमा हो गया था. जिससे राहगीरों के साथ साथ स्कूली बच्चों को घर पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जलजमाव के कारण बीच सड़क पर वाहन बंद हो जाने से काफी तकलीफ हुई। भारी बारिश से एक बार फिर नदी-नालों में उफान आने की संभावना प्रबल हो गई है। जानकारी के अनुसार, पिछले तीन माह से रुक-रुक कर बारिश होती रही। 23 अगस्त को भी जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी, जो दोपहर में मूसलाधार बरसने लगी। शाम 4 बजकर 45 मिनट तक लगातार होती रही। लोगों को एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाने का मौका नही मिल रहा था, जो जहां था, लगातार पांच घंटे तक फंसा रहा। इसके कारण चहुंओर पानी ही पानी देखने को मिल रहा था। इस दौरान लोगों का कहना था कि बारिश तो बहुत देखी, लेकिन लगातार इतने देर तक मूसलाधार बारिश अभी तक नही देखी थी। लगातार हो रही बारिश के कारण पहले से उफान पर रहे नदी-नालों के और उफान पर आने की संभावना है। खासकर स्वर्णरेखा नदी, बुरुडीह डैम में देर रात तक पानी के स्तर में बेतहाशा वृद्वि होने की संभावना प्रबल हो

सड़क पर जमा पानी ● फोटोन न्यूज

बरसात से चक्रधरपुर-राउरकेला सड़क बंद

सड़क पर खड़े स्कूली छात्र ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को सुबह से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। नदी-नाले उफान पर हैं और चक्रधरपुर - राउरकेला मार्ग (एनएच 320डी) स्थित सोनुवा थाना क्षेत्र के झाड़गांव पुलिया से पानी ओवरफ्लो होने के कारण दोपहर 12 बजे से आवागमन पूरी तरह बाधित है। इस वजह से लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर भारी बारिश की वजह से शुक्रवार को गोइलकेरा में साप्ताहिक हाट भी नहीं लग सका। इससे ग्रामीणों को जरूरी सामानों की खरीददारी में परेशानी झेलनी पड़ी। स्कूली बच्चों को भी भारी बारिश के कारण स्कूल जाने में कठिनाई हुई। इधर, मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से झारखंड के 14 जिलों में 22 से 24 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम सिंहभूम जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। विभाग ने बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

भादो महोत्सव पर हुआ मंगलपाठ राणी सती को लगे छप्पन भोग

मंगलपाठ में शामिल महिलाएं ● फोटोन न्यूज

CHAIBASA : दो दिवसीय भादो अमावस्या महोत्सव पर परम आराध्य श्री राणी सती दादी जी के पूजन समारोह में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महोत्सव के पहले दिन शुक्रवार को श्री राणी सती मंदिर में संगीतमय मंगल पाठ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में राजस्थानी महिलाएं व युवतियां शामिल हुईं। शुक्रवार को 3 बजे सर्वप्रथम परम आराध्य दादी जी की ज्योत प्रज्वलित की गई। इसके बाद श्रद्धालु मंगल पाठ में शामिल हुए, जो लगभग 3 घंटे चला। चांदमारी स्थित श्री राणी सती मंदिर को फूलों और रंगबिरंगी लाइटों से सजाया गया है। राणी सती दादी को छप्पन भोग चढ़ाए गए। श्रद्धालुओं ने दरबार में माथा टेक प्रसाद ग्रहण किया। चक्रधरपुर के कलाकारों ने श्रद्धालुओं को खूब झुमाया। मंदिर परिसर में मंगल पाठ के दौरान चक्रधरपुर के धर्मेंद्र केजरीवाल एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को खूब झुमाया।

BRIEF NEWS

मोतिहारी में 25 को लगेगा जॉब कैंप

EAST CHAMPARAN : जिला नियोजनालय परिसर में आगामी 25 अगस्त 2025 को 11:00 बजे एक दिवसीय जॉब कैंप सह कैरियर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया जायेगा। जॉब कैम्प में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा कलेक्शन ऑफिसर पद के लिए योग्य अभ्यर्थियो का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए योग्यता 12 वीं पास निर्धारित है,साथ ही उन्हे ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियो के लिए उम्र सीमा 18-32 वर्ष (पुरूष) निर्धारित है। जॉब का कार्यस्थल बिहार के पूर्वी चम्पारण व गोपालगंज जिला होगा। चयनित अभ्यर्थियो का मानदेय 16000+ सीटीसी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ अन्य सुविधाएं जैसे आवास, इंसेंटिव, पीएफ, मेडिकल देय होगा। जॉब कैंप मे कुल 150 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थी चयनित किये जायेगे।

दहेज हत्याकांड में नई कार्रवाई, दो महिला आरोपी भेजी गई जेल

DARBHANGA : जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब तक हिरासत में ली गई सास और ननद को सोमवार को जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से गांव में हलचल तेज हो गई है। हालांकि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। दूसरी ओर मृतका के परिजन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आश्चर्य जताया कि मुख्य अभियुक्त अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने मांग की है कि फरार आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। पुलिस का कहना है कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।

पर्युषण लौकिक नहीं, आध्यात्मिक पर्व : सुशील बाफना

ARRARIA : फारबिसगंज तेरापंथ भवन में कोलकाता से आए हुए उपासक सुशील बाफना और सुमेरमल बैद की उपस्थिति में शुक्रवार को पर्युषण महापर्व का तीसरा दिन सामायिक दिवस के रूप में मनाया गया। पर्युषण पर्व लौकिक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक पर्व है। जिसे त्याग तपस्या और संयम के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरूआत महिला मंडल के द्वारा पर्युषण पर्व के सामायिक दिवस पर आधारित गीतिका से की गई। मौके पर मुख्य उपासक सुशील बाफना ने कहा कि सामायिक की महत्ता सभी जैन धर्म ग्रंथो आगमों में गाई गई है। सामायिक का शाब्दिक अर्थ है समता की आय करना। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करना सामायिक है। माया से रहित होकर समता से बैठना सामायिक है। सामायिक में लीन व्यक्ति आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ता है सामायिक में व्यक्ति छह जीवकायों को अभयदान देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा-

नालंदा, राजगीर, गयाजी तक विदेशी पर्यटकों को पहुंचने में नहीं होगी दिक्कत

AGENCY GAYAJI : बिहार के गयाजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व मध्य रेल की नई बुद्ध सर्किट फास्ट मेमो ट्रेन (03626) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का परिचालन वैशाली से कोडरमा के बीच होगा और यह हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर, इमलैया, गया, गुरपा और कोडरमा कुल 14 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को सीधे जोड़ेगी और इससे विदेशी पर्यटकों और बौद्ध धर्म के अनुयाइयों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। दुनिया के 20 से अधिक देशों में बौद्ध आबादी बड़ी संख्या में है। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, लाओस, भूटान और मंगोलिया जैसे देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। जापान, चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसे देशों में भी करोड़ों की संख्या में बौद्ध रहते हैं। इन देशों से हर साल हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक बिहार आते हैं। नई ट्रेन शुरू होने से नालंदा, राजगीर और गया जैसे स्थलों तक विदेशी पर्यटकों की आसान पहुंच संभव होगी। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। बौद्ध धर्म के इन ऐतिहासिक स्थलों से विदेशी आगंतुकों का जुड़ाव बिहार को सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी नई पहचान देगा। नालंदा प्राचीन काल में एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र रहा है, जहां हजारों भिक्षु और विद्वान अध्ययन करते थे। राजगीर और वैशाली जैसे स्थल बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन धर्म के भी केंद्र रहे हैं। गया का महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन सभी स्थलों तक रेलवे संपर्क मजबूत होने से बिहार का अंतरराष्ट्रीय महत्व और बढ़ेगा। चुनावी दृष्टि से भी इस ट्रेन की अहमियत मानी जा रही है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच बुद्ध सर्किट ट्रेन की शुरूआत को सरकार एक बड़े कदम के रूप में पेश कर रही है। यह ट्रेन बौद्ध धर्मावलंबियों और विदेशी पर्यटकों को जोड़ने के साथ-साथ स्थानीय जनता को सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने वाले इस फैसले का सीधा असर बिहार की राजनीति और समाज पर पड़ सकता है।

केंद्र की ओर से बिहार को मिला पूरा सहयोग : नीतीश कुमार

GAYAJI : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से बिहार को 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिलने पर खुशी जताई। गयाजी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गयाजी में कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गयाजी में अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है।इस साल के बजट में भी बिहार को स्पेशल पकेज मिला है। बिहार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बहुत ज्यादा काम कर दिया है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सभी क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। हाल ही में कुछ नए काम भी करवाए गए हैं। कुछ नए फैसले लिए गए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना किया गया है। मुख्यमंत्री कहा कि गया का नाम हमने गयाजी करवाया। पहले शहर का नाम गया ही था। अब इसका नाम गयाजी हो गया है। एक तरफ बोधगया है, दूसरी ओर गयाजी।

दो आपराधिक गिरोहों के बीच गैंगवार, डबल मर्डर, सड़क जाम

AGENCY EAST CHAMPARAN : जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित पश्चिमी मधुबनी पंचायत के दरियापुर रामचुनिया मठ के समीप गुरुवार की रात करीब साढे नौ बजे दो अपराधी गिरोह के बीच आपसी वर्चस्व में गोलीबारी की घटना हुई, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने हत्याकांड के आरोपित धनंजय गिरी समेत दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में गुड्डू यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल धनंजय गिरी ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया।
धनंजय पर हत्या व लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं।वही इस दोहरे हत्याकांड से आक्रोशित परिजन शुक्रवार को धनंजय गिरि व गुड्डू यादव के शव को भादा चौक पर रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे है। परिजन हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे है। घटना को लेकर एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जांच में यह सामने आया है,कि हरसिद्धि के झाड़वा निवासी सनावर खान नामक 25 हजार का इनामी बदमाश ने धनंजय गिरि को फोन कर बुलाया था। अरेराज डीएसपी रवि कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर छापेमारी की जा रही है। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
एसडीपीओ रवि कुमार ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियो की पहचान कर ली गयी है। गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। इधर हत्याकांड को लेकर व्याप्त तनाव और आक्रोश के मद्देनजर कई थाना की पुलिस गांव में कैप कर रही है।

भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम, उत्साहित दिखे राहुल गांधी

AGENCY BHAGALPUR : राजनीति और सामाजिक सरोकार दोनों के लिहाज से शुक्रवार का दिन भागलपुर के लिए खास रहा। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव आज भागलपुर पहुंचे। इस यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। भीड़ में एक अनोखा वाकया भी सामने आया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल, जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे और लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक महिला ने मीडिया से कहा कि वह यहां राहुल गांधी को नहीं बल्कि राजीव गांधी को देखने आई हैं। महिला का यह बयान सुनते ही आसपास मौजूद भीड़ चौंक गई और देखते ही देखते लोग उसके इर्द-गिर्द जमा होने लगे। यह नजारा वहां मौजूद सभी पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया।

वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी व अन्य

यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के कई स्थानीय नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। एक नेता ने कहा कि यह आंदोलन अब उग्र आंदोलन का रूप ले चुका है। उनका कहना था कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अपनी मांगों और हक के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। नेताओं ने यह भी कहा कि चाहे माय बहन योजना हो या देश की अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं, वे तभी सफल हो सकती हैं जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सत्ता में हों। भीड़ से मिल रहे जनसमर्थन को देखते हुए यह भी दावा किया गया कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक होगा। वहीं जनता की उम्मीदें और सवाल महिला का राजीव गांधी वाला बयान एक प्रतीकात्मक रूप से भी देखा जा रहा है।

अब भगोड़े अपराधी भी नहीं बच पाएंगे, दूसरे राज्यों से दबोचे गए 64 कुख्यात : कुंदन कृष्णन

AGENCY PATNA : बिहार में अपराध करके दूसरे राज्य भागने वाले अपराधी भी अब नहीं बच रहे हैं। इस वर्ष जनवरी से 20 अगस्त तक ऐसे 64 अपराधियों को एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुख्यात और इनामी अपराधी भी शामिल हैं। यह जानकारी एडीजी (अभियान) सह एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा 14 की संख्या में अपराधियों को दिल्ली से दबोचा गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से 9, उत्तर प्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5, महाराष्ट्र से 4, मध्य प्रदेश से 4, हिमाचल प्रदेश से 2, पंजाब से 2 के अलावा राजस्थान, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर से 1-1 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी कृष्णन ने कहा कि राज्य में नक्सली हिंसा में काफी कमी आने के बाद से एसटीएफ को संगठित अपराध और इससे जुड़े अपराधियों का समूल नाश करने में लगा दिया गया है। राज्य के अंदर पनप रहे सभी तरह के संगठित अपराधों को खत्म करने में इसकी भूमिका बेहद अहम है और इसकी उल्लेखनीय उपलब्धि की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। पिछले वर्ष अपराधियों से मुठभेड़ के 8 मामले सामने आए थे। इस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पिछले वर्ष 2024 में की गई कार्रवाई में 752 अपराधियों को दबोचा गया था, लेकिन इस वर्ष अब तक 857 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह 2024 में 44 और 2025 में अब तक 101 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है।

नागरिक संघर्ष समिति ने बैठक में रखी वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की मांग

AGENCY ARARIA : रेलवे बोर्ड के पूर्णिया से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन परिचालन की घोषणा का अररिया के विभिन्न संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है।ट्रेन को पूर्णिया के बजाय जोगबनी से परिचालन को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार होने लगी है।इसी कड़ी में रेलवे के विकास और यात्री सुविधाओं को लेकर संघर्ष करने वाली फारबिसगंज की संस्था नागरिक संघर्ष समिति ने शुक्रवार को फैंसी मार्केट के एक गेस्ट हाउस में समिति के अध्यक्ष शाहजहां शाद की अध्यक्षता में मीटिंग की, जहां एक स्वर से सभी सदस्यों ने इस घोषित ट्रेन का विस्तार जोगबनी तक किए जाने हेतु चरणबद्ध आंदोलन करने पर अपनी सहमति जताई। उल्लेखनीय है की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के आलोक में यह ट्रेन पटना से खगड़िया ,सहरसा, मधेपुरा, बनमनखी के रास्ते पूर्णिया तक आएगी। पूर्णिया से जोगबनी की दूरी महज 80 किलोमीटर है।यदि इस ट्रेन का विस्तार जोगबनी तक किया जाता है तो पूरे अररिया जिला समेत सीमावर्ती नेपाल के हजारों रेल यात्री लाभान्वित होंगे और ट्रेन की उपयोगिता भी शत प्रतिशत होने की गारंटी रहेगी।

NEWS BOX

बाढ़ राहत राशि को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा

AGENCY BHAGALPUR : जिले में बाढ़ से सबौर प्रखंड क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है, जहां दर्जनों घर गंगा की धारा में विलीन हो चुके हैं। लोग खुले आसमान के नीचे आश्रय खोजने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राहत स्वरूप अनुदान राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। यह पैसा सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजा जाना था, लेकिन सबौर प्रखंड के कई ग्रामीणों के खातों में अब तक राशि नहीं पहुंची। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण सबौर ब्लॉक पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जब तक सभी पीड़ित परिवारों को बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका आरोप है कि कई परिवार बाढ़ की मार झेल रहे हैं, घर-बार उजड़ गए, खाने-पीने तक का संकट खड़ा हो गया, लेकिन सरकार द्वारा घोषित राशि अभी तक उनके खाते में नहीं आई है।

भादो महोत्सव के दूसरे दिन मंगल पाठ, सजा राणीसती दादी का दरबार

AGENCY ARARIA : फारबिसगंज के श्री लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी में श्री दादी जी महिला मंडल द्वारा आयोजित दो दिवसीय श्री राणीसती भादो महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को मंगलपाठ का आयोजन किया गया।मौके पर राणीसती दादी का भव्य दरबार सजाया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में सिलीगुड़ी से आये गायक रितेश खंडेलवाल और संतोष देवी खंडेलवाल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति कर माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। इसके साथ ही दिनभर जात एवं पूजन कार्यक्रम चलता रहा। इससे पूर्व मंगल पाठ का शुभारंभ मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक दुबे की अगुवाई मुख्य यजमान रविंद्र अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी रेखा अग्रवाल के द्वारा दीप व ज्योति प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भक्तों के लिए मंदिर परिसर में सेल्फी पॉइंट बना गया था, जहां भक्तों की काफी भीड़ नजर आई। इस अवसर पर मीणा अग्रवाल, उर्मिला जैन, किरण भूपाल, स्नहेलता शर्मा, लक्ष्मी गौतम, पिंकी अग्रवाल, संगीता फोगला, नीलम डालमियां सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष भक्तगण मौजूद थे।

एबीवीपी ने एसएनएस आरकेएस कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान

AGENCY SAHARSA : राष्ट्र हित के लिए प्रेरित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने स्थानीय सर्व नारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय में शुक्रवार को सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व कॉलेज अध्यक्ष गणेश यादव और कॉलेज मंत्री रोशन कुमार ने किया। वही नगर मंत्री अंशु कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान इस वर्ष आगामी 31 अगस्त तक चलेगा। सदस्यता अभियान में जुड़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को साथ लेकर परिषद आगामी शैक्षणिक सत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगा।हमारा लक्ष्य 'छात्रों के लिए, छात्रों द्वारा और छात्रों के माध्यम से' देश की सेवा करना है।परिषद का उद्देश्य छात्रों को संगठन से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। कॉलेज अध्यक्ष गणेश यादव ने कहा कि एबीवीपी का सदस्यता अभियान महज एक संगठन से जुड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ,परिषद ने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा काम किया है और उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक बनने का काम करती है।

डीएम ने जल-जीवन-हरियाली को लेकर की समीक्षा बैठक

AGENCY SAHARSA : जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण,जल संरक्षण,ऊर्जा संरक्षण एवं अन्य बहुआयामी लक्ष्यों के प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों व संचालित योजनाओं की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत संचालित कुल पन्द्रह विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि प्राप्त करने हेतु ठोस कारवाई करने एवं तत्संबंधी पूर्णता से संबंधित योजनाओं को पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में ब्रेडा से संबंधित तकनीकी पदाधिकारी को विभिन्न भवनों में संस्थापित सौर प्लेट की क्रियाशीलता की जांच करने, तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी को सभी संबंधित तालाबों को एक सप्ताह के भीतर साफ कराने हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है।

प्रशिक्षण

दिव्यांगजनों को आपदा सुरक्षा को लेकर दी गई ट्रेनिंग

बाढ़ की स्थिति में बचाव की बताई तकनीक

AGENCY ARARIA : अररिया बुनियाद केंद्र में शुक्रवार को दिव्यांगजनों के लिए आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरक्षित शुक्रवार का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता (आपदा) नवलीन कुमार, एडीएमओ (आपदा) मृत्युंजय कुमार,बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शंभु कुमार रजक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सूरज कुमार, जिला प्रबंधक सक्षम नवीन कुमार नवीन तथा उपस्थित दिव्यांग लाभार्थी फूलकुमारी देवी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया।

- आपदा की अन्य परिस्थितियों से निपटने के लिए जागरूकता और सुरक्षा उपायों की दी गई जानकारी
- कार्यक्रम में 28 दिव्यांगजन अपने सहयोगियों एवं परिजनों के साथ हुए शामिल

मौके पर पर एसडीआरएफ के उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार अपनी टीम सिपाही चंदन कुमार, रविन्द्र कुमार, रामनरेश पासवान एवं हेमराज के साथ उपस्थित रहे और प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण की शुरूआत में बाढ़ या डूबने जैसी आपदा से बचाव की तकनीक प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा आपदा की अन्य परिस्थितियों से निपटने हेतु जागरूकता एवं सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में सम्मिलित जिला दिव्यांग आइकॉन डॉ साबरा तरन्नुम भी सम्मिलित हुई, उनके द्वारा अररिया के सभी दिव्यांगजनों से अनुरोध किया गया कि इस प्रशिक्षण में अवश्य सम्मिलित हों, आपदा के समय यह प्रशिक्षण बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।
कार्यक्रम में 28 दिव्यांगजन अपने सहयोगियों एवं परिजनों के साथ शामिल हुए। इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में जीविका की सामाजिक कार्य प्रबंधक चंदा कुमारी, सीनियर फिजियो तरन्नुम निगार, टेक स्पीच एंड हियरिंग विशेषज्ञ कुमार साहेब सहित सुरक्षा प्रहरी राजा एवं विजय तथा सफाईकर्मी चंदन का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बुनियाद केंद्र सक्षम एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के फ्लैट पर छापेमारी

AGENCY BHAGALPUR : बिहार पुलिस की आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग की टीम ने शुक्रवार को भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के भागलपुर के खंजरपुर समेत राज्य में उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है।
आज सुबह से आरंभ हुई यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर है। विनय सौरभ के विरुद्ध भ्रष्ट और अवैध तरीके से आय के स्रोतों से 1 करोड़ 43 लाख 78 हजार रुपये मूल्य की परिसंपत्ति अर्जित की है। जो उनके आय से करीब 188.23 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इसी आरोप में आर्थिक अपराध थाना, पटना में 21 अगस्त 2025 को केस दर्ज की गई थी।
सुरक्षा दृष्टिकोण से बरारी के खंजरपुर स्थित अभिनव एनक्लेव वाले विनय सौरभ के फ्लैट पर काफी संख्या में पुलिस जवानों को लगाया गया है। निबंधन कार्यालय के बाहर भी किसी को जवान प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। अंदर से कोई बाहर और बाहर से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत वहां तैनात सुरक्षाकर्मी नहीं दे रहे हैं। प्रारंभिक छापेमारी में तीन करोड़ से अधिक अर्जित संपत्ति का पता चला है।

जीविका की केस राइटिंग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण

ARRARIA : जीविका की ओर से जीविका दीदियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की कहानी को कलमबद्ध करने के उद्देश्य से कैडर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को जिला कार्यालय स्थित एफटीआईसी हॉल में करवाया गया। इस प्रशिक्षण में प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण शैलेन्द्र कुमार एवं प्रबंधक संचार नारायण कुमार के द्वार कैडर्स को विस्तार से बताया गया कि जीविका दीदियों की सफलता की कहानियों को कैसे लिखा जाये ताकि अधिकझसे-अधिक लोग उसे पढकर समझ सके और उससे प्रेरणा लेकर दूसरी दीदियां भी आगे बढ़ सके। इस प्रशिक्षण में सभी नौ प्रखंडों से तीन-तीन कैडर्स को बुलाया गया था।

आत्मनिर्भर, सशक्त और अवसरों से परिपूर्ण भारत गढ़ने का संकल्प

भारत आज उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां से उसकी दिशा सीधे वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर जाती दिखाई देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बीते पचहत्तर वर्षों में देश ने तमाम उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हाल के वर्षों में जिस गति से भारत ने अपनी आर्थिक, सामरिक, तकनीकी और सामाजिक क्षमता को परिपक्व किया है, वह किसी भी राष्ट्र के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणा इसी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना न केवल एक नीतिगत पहल है, बल्कि यह उस व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और अवसरों से परिपूर्ण समाज के रूप में गढ़ने का संकल्प लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यह घोषणा उस विश्वास का प्रतीक है कि भारत का भविष्य उसके युवाओं में निहित है। यह विश्वास ही हमें उस लक्ष्य तक ले जाएगा, जहां भारत न केवल अपने नागरिकों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि विश्व को भी शांति, प्रगति और मानवीय मूल्यों की दिशा दिखाएगा। यह योजना एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से लागू की जा रही है और इसके अंतर्गत आने वाले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली नजर में यह घोषणा महज एक सरकारी कार्यक्रम लग सकती है, लेकिन गहराई से देखें तो यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसकी सामाजिक संरचना और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षाओं से सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के महाशक्ति बनने का मार्ग उसके युवाओं के हाथों से होकर गुजरता है। युवाओं के लिए भी यह अवसर है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच मिला हुआ है, जिसमें कि यदि उनके श्रम को उचित सम्मान प्राप्त है, तो न केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि होती है, बल्कि राष्ट्र का सामूहिक उत्थान भी सुनिश्चित होता है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और नीतिगत आकलनों के अनुसार जो अतिशीघ्र दुनिया की तीसरी अर्थ ०?यवस?था बन जाएगा। यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि इस तथ्य का प्रमाण है कि भारत का उत्पादन, उसका निर्यात, उसकी सेवा क्षमता और उसका घरेलू बाजार अभूतपूर्व विस्तार की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से जूझ रही है, भारत की विकास दर सबसे ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थान भी स्वीकार कर चुके हैं कि विश्व की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन आज भारत है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति और वैश्विक छवि भी आज ऐसी है, जो हमारे महाशक्ति बनने की संभावनाओं को बल देती है। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे विकसित राष्ट्र भारत को अपने विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स और जी-20 जैसे मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत ने जो प्रगति की है, वह आने वाले वर्षों में विश्व को दिशा दिखाने वाली होगी। ऐसे में यदि देश का आंतरिक ढांचा, विशेषकर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का ढांचा मजबूत होता है, तो भारत के लिए वैश्विक महाशक्ति बनने का मार्ग और भी सरल हो जाएगा। वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उसमें यह विकसित भारत रोजगार योजना भारत की वृद्धि को और अधिक गहराई तक समाज में पहुंचाने का माध्यम बनेगी। इसका भाग ए सीधे उन युवाओं को लक्षित करता है, जो पहली बार रोजगार की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे युवा, जो अभी-अभी शिक्षा पूरी करके जीवन की नई पारी की शुरूआत कर रहे हैं, उन्हें दो किस्तों में पंद्रह हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह न केवल उनके आर्थिक बोझ को हल्का करेगा, बल्कि उन्हें वित्तीय साक्षरता के महत्व से भी अवगत कराएगा। योजना का यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में युवा अक्सर नौकरी मिलने के बाद भी बचत और निवेश की आदत विकसित नहीं कर पाते। इस प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत खाते में जमा रहना अनिवार्य होगा, जिससे उनमें वित्तीय अनुशासन की आदत डाली जा सके। योजना का दूसरा भाग नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने वाला है। जब तक उद्योग और सेवा क्षेत्र नए रोजगार सृजित नहीं करेंगे, तब तक युवाओं के सपनों को ठोस धरातल नहीं मिल सकता। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह नियोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए तैयार है। यदि कोई कंपनी नए कर्मचारी नियुक्त करती है और उसका वेतन एक लाख रुपये तक है, तो सरकार दो वर्षों तक प्रति कर्मचारी तीन हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता करेगी। विनिर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस प्रोत्साहन को चार वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था स्पष्ट करती है कि भारत केवल सेवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान को गति देकर विनिर्माण को भी अपनी आर्थिक रीढ़ बनाना चाहता है। आज देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार की अधिकांश प्रमुख योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं (पीएलआई) इसके उदाहरण हैं। इन योजनाओं ने समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में परिवर्तन लाने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से भी यही अपेक्षा है कि यह न केवल घोषणाओं तक सीमित रहेगी, बल्कि युवाओं को वास्तविक अवसर भी उपलब्ध कराएगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि योजना का व्यापक प्रभाव भारत की सामाजिक संरचना पर भी पड़ेगा। वस्तुतः यह भी एक तथ्य है कि हमारे देश में आज भी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा बहुत बड़ा है।

दक्षिण चीन सागर की लहरों पर भारत का बढ़ता प्रभाव

ANALYSIS

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

हाल ही में स्कारबोरो शोल के पास फिलिपींस तटरक्षक की एक नाव को परेशान करने की कोशिश कर रहे चीनी नौसैनिक और तटरक्षक जहाज आपस में ही टकरा गए। यह घटना दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके नतीजों का स्पष्ट उदाहरण है। फिलिपींस के बीआरपी सुलुआन जहाज का वहां होना, मछुआरों को सहायता और आपूर्ति पहुंचाने के लिए था, लेकिन चीन की मिलिट्री कोएर्शन नीति के तहत वहां चीनी जहाजों का आना-जाना आम हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत और फिलिपींस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एक साहसिक संदेश लेकर आया कि दक्षिण चीन सागर अब केवल चीन और उसके दावों का खेल का मैदान नहीं रहेगा। दक्षिण चीन सागर, एशिया का वह सामरिक मोर्चा है, जहां भूगोल, संसाधन और शक्ति राजनीति तीनों का संगम होता है। यहां हर साल लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापारिक माल गुजरता है। ऊर्जा के बड़े भंडार, समृद्ध मत्स्य संसाधन और रणनीतिक जलमार्ग इसे वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनाते हैं। चीन नाइन-डैश लाइन के नाम पर इस पूरे क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकार जताता है, जबकि फिलिपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे देश भी अपने-अपने हिस्सों का दावा करते हैं।

दक्षिण चीन सागर के उफनते पानी में भारत का झंडा अब केवल समुद्री हवाओं में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की हलचलों में भी लहराने लगा है। ब्रिटेन में फिलिपींस के राजदूत और पूर्व विदेश मंत्री टेडोरो लॉक्सिन जूनियर ने हाल ही में भारत-फिलिपींस के पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के बाद जिस खुलेपन से भारतीय नौसेना की सराहना की, वह केवल एक राजनयिक बयान नहीं। यह उस बदलते सामरिक समीकरण का संकेत है, जिसमें भारत अब एक साहसिक समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। लॉक्सिन का यह कहना कि भारतीय नौसेना एकमात्र ऐसी नौसेना है, जो जहां चाहती है, वहां जाती है सीधे तौर पर उस आत्मविश्वास की तरफ इशारा करता है, जिसे भारत ने पिछले एक दशक में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थापित किया है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब फिलिपींस के जलक्षेत्र में तनाव चरम पर है। हाल ही में स्कारबोरो शोल के पास फिलिपींस तटरक्षक की एक नाव को परेशान करने की कोशिश कर रहे चीनी नौसैनिक और तटरक्षक जहाज आपस में ही टकरा गए। यह घटना दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके नतीजों का स्पष्ट उदाहरण है। फिलिपींस के बीआरपी सुलुआन जहाज का वहां होना, मछुआरों को सहायता और आपूर्ति पहुंचाने के लिए था, लेकिन चीन की मिलिट्री कोएर्शन नीति के तहत वहां चीनी जहाजों का आना-जाना आम हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत और फिलिपींस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एक साहसिक संदेश लेकर आया कि दक्षिण चीन सागर अब केवल चीन और उसके दावों का खेल का मैदान नहीं रहेगा। दक्षिण चीन सागर, एशिया का वह

सामरिक मोर्चा है, जहां भूगोल, संसाधन और शक्ति राजनीति तीनों का संगम होता है। यहां हर साल लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापारिक माल गुजरता है। ऊर्जा के बड़े भंडार, समृद्ध मत्स्य संसाधन और रणनीतिक जलमार्ग इसे वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनाते हैं। चीन नाइन-डैश लाइन के नाम पर इस पूरे क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकार जताता है, जबकि फिलिपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे देश भी अपने-अपने हिस्सों का दावा करते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में फ्रीडम आफ नेविगेशन के नाम पर नौसैनिक गश्त तो करते हैं, लेकिन वे चीन की संवेदनशील जगहों पर खुले टकराव से बचते हैं। इसके उलट, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने युद्धपोतों और आपूर्ति जहाजों के जरिए बार-बार यह दिखाया है कि वह किसी भी समुद्री क्षेत्र में, चाहे वह चीन के दावे के भीतर क्यों न हो, अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहेगा। भारत और फिलिपींस का यह पहला नौसैनिक अभ्यास केवल रक्षा सहयोग का आरंभ नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक स्टेटमेंट है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब पूर्व का दावा करें में बदल रही है। यह परिवर्तन महज नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक यथार्थ का परिणाम है। चीन का आक्रामक रवैया और अमेरिका की हिचकिचाहट के बीच, दक्षिण-पूर्व एशिया के देश ऐसे साझेदार की तलाश में हैं, जो न केवल उनके साथ खड़ा हो, बल्कि उनके साथ मैदान में भी उतरे। भारत इस भूमिका में फिट बैठता है, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्र विदेश नीति और मजबूत सैन्य क्षमता के साथ। लॉक्सिन के बयान में पश्चिमी देशों की नौसेनाओं पर कटाक्ष भी छिपा था। कास्त्राती शब्द का प्रयोग उन्होंने महज व्यंग्य के लिए नहीं किया, बल्कि यह दिखाने के लिए किया कि पश्चिमी ताकतें आवाज तो बुलंद करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर चीन के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में हिचकिचाती हैं। इसके विपरीत, भारत बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन के भी वहां पहुंच जाता है, जहां उसके मित्र को मदद की जरूरत होती है। यही कारण है कि लॉक्सिन ने खुले तौर पर कहा कि फिलिपींस का साहस उसकी ताकत है, लेकिन इस गश्त में शामिल होने की हिम्मत केवल भारतीयों में है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि भारत-फिलिपींस संबंध केवल आज की रणनीति का नतीजा नहीं हैं। दोनों देशों ने 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तब से सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर संबंध बढ़ते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है, फिलिपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का अनुबंध किया है, जो चीन के समुद्री ठिकानों पर त्वरित और सटीक वार करने में सक्षम है। यह सौदा न केवल सैन्य क्षमता बढ़ाने वाला है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का भी प्रमाण है। लॉक्सिन का वूंडेड नी नरसंहार का जिक्र भी एक गहरे संदेश के साथ था। यह 1890 की वह घटना थी जिसमें अमेरिकी सेना ने दक्षिण डकोटा में मूल अमेरिकी जनजाति लकोटा सिउक्स के 150 से 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लॉक्सिन ने यह संकेत देने की कोशिश की कि अमेरिका का इतिहास अपने सहयोगियों और मूल निवासियों के साथ विश्वासघात से भरा है और आज भी उसकी विदेश नीति में वही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यह टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से यह बताती है कि फिलिपींस जैसे देश अमेरिका पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते और भारत उनके लिए एक अधिक विश्वसनीय साझेदार हो सकता है। भारत की समुद्री रणनीति अब हिंद महासागर से आगे बढ़कर प्रशांत महासागर तक फैल रही है। यह केवल सामरिक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका है। इसका अर्थ यह है कि भारत केवल अपने हितों की रक्षा नहीं करता, बल्कि मित्र देशों की समुद्री सुरक्षा का भी जिम्मा उठाता है। कहना होगा कि यह भूमिका निभाना आसान नहीं है, इसमें नौसैनिक क्षमता, आर्थिक संसाधन और राजनीतिक इच्छाशक्ति, तीनों की आवश्यकता होती है। पिछले एक दशक में भारत ने इन तीनों मोर्चों पर अपनी तैयारी सिद्ध की है। वस्तुतः टेडोरो लॉक्सिन का यह बयान अंततः उस भरोसे की अभिव्यक्ति है, जो भारत ने अपने आचरण और नीतियों से अर्जित किया है। दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति अब केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक है। उसकी यह उपस्थिति आगे फिलिपींस, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती है। पश्चिमी ताकतों की हिचकिचाहट के बीच भारत का यह आत्मविश्वास आने वाले वर्षों में एशिया-प्रशांत के शक्ति संतुलन को नई दिशा दे सकता है। जहां पश्चिमी देश रणनीतिक दस्तावेजों और बयानबाजी में उलझे हैं, वहीं भारत लहरों पर अपने कदमों के निशान छोड़ रहा है, कभी मित्र देशों के तट पर, तो कभी विवादित जलक्षेत्रों के बीच। आज यह केवल एक नौसेना की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की दास्तान है, जो अब वैश्विक मंच पर अपनी जगह खुद तय कर रहा है और यही वह कारण है कि दक्षिण चीन सागर की लहरों में आज भारतीय नौसेना का नाम साहस और भरोसे के पर्याय के रूप में गूंज रहा है।

किसानों के हित में तनकर खड़ा भारत

अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत की अनिश्चितता के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह स्पष्ट किया कि वह किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा में दीवार की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत उनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में कृषि और डेरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत मांग रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देते हुए कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ-साथ अमेरिकी डेरी उत्पादों की भारत में पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के आदेश के बाद पीएम मोदी का यह वक्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि ट्रंप का यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा, जिसके बाद कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत हो जाएगी। अमेरिका भारत में अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार चाहता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह डेरी क्षेत्र और जीएम सोयाबीन और मक्का के लिए अपना बाजार नहीं खोलेगा। अमेरिका में पशु आहार का उपयोग डेरी क्षेत्र में किया जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने पहले के किसी भी व्यापार समझौते में कभी भी शुल्क की कोई रियायत नहीं दी है। भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा अमेरिका द्वारा मवेशियों को पशु उत्पाद खिलाने की प्रथा को लेकर भी चिंताएं हैं, जो स्थानीय मानदंडों और सुरक्षा संबंधी धारणाओं का उल्लंघन करती हैं। डेरी क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रतिबंधित मांस पदार्थों का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कड़े रुख अपनाने के कारण कृषि और देश के स्वाभिमान से जुड़े प्रश्नों को दरकिनार कर किसी समझौते की संभावना मुश्किल है। अमेरिका का आग्रह चीन को अपने निर्यात में गिरावट को लेकर उसकी चिंता से उपजा है। अमेरिका के सोयाबीन निर्यात में चीन का लगभग 55 प्रतिशत और मक्का निर्यात में 20 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका भारत से संपर्क करके अपने खरीदार आधार का विस्तार करना चाहता है। कृषि व्यापार में भारत का अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 6.25 अरब डालर रहा, जो 2023-24 में 5.52 अरब डालर था। वहीं कैलेंडर वर्ष 2023 में अमेरिका का भारत को निर्यात 37.3 करोड़ डालर था। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 86.51 अरब डालर था, जबकि अमेरिका से आयात कुल 45.69 अरब डालर था। आज भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां वह एक छोर से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था से मुक्ति मिल सके। भारत के लिए कपड़ा, चमड़ा, जूते-चप्पल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए राहत सुनिश्चित करना एक प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है। इसी बीच पैकेज के हिस्से के रूप में जीएम सोयाबीन और मक्का के निर्यात को शामिल करने के अमेरिका के आग्रह ने वार्ता पर लंबी छाया डाल दी है। अमेरिका से व्यापार वार्ता में जीएम फसलें भी एक सीमा रेखा बनी हुई हैं। भारत ने वैश्विक बाजार में एक गैर-जीएम उत्पादक के रूप में विशेष रूप से सोया, खली निर्यात में एक विशिष्ट स्थान बनाया है, जहां खरीदार सक्रिय रूप से प्राकृतिक किस्मों की तलाश करते हैं। भारत में मक्का से एथेनाल कम मात्रा में बनता है और अधिकतम मानव आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। जब पंजाब के लोग नशा विरोधी आंदोलन में पूरी तरह डूबे हुए हैं, तब जीएम के जरिए पंजाब की मिट्टी, पानी और हवा को और जहरीला बनाने की कोशिश बेहद निंदनीय है। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे अप्राकृतिक बता चुका है। भारत में अभी तक केवल जीएम फसलों के रूप में बीटी कपास की ही व्यावसायिक खेती हो रही है। 2010 में बीटी बैंगन को भी मंजूरी दिलाने की कवायद शुरू हुई थी, पर नौ राज्य सरकारों, कई पर्यावरण विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और किसानों के व्यापक विरोध के कारण सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके विरोध में आ गए हैं। विश्व के अन्य भागों में भी जीएम फसलों के परीक्षण अच्छे साबित नहीं हुए हैं। अमेरिका में एक प्रतिशत भू-भाग में जीएम मक्का की खेती की गई, जिसने 50 प्रतिशत गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपनी जमीन पर धान एवं मक्के की खेती की, मगर पांच-छह वर्षों में ही वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 2014 के बाद वहां से जीएम खेती लगभग बंद करनी पड़ी। इसे देखते हुए भारत का अपने किसानों के हित में अमेरिका के सामने सख्त रुख अपनाना समय की मांग है।

Social Media Corner

सच के हक में...

श्री स्वराज पॉल जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं। ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जनसेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा। मुझे हमारी अनेक मुलाकातें याद आती हैं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ॐ शांति।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

भारत के प्रिय मतदाताओं, मैं आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं- जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा कभी जनसेवा हो सकता है? नहीं ना। उन्हें आपके वोट की जरूरत ही नहीं, इसलिए आपकी समस्याओं की परवाह भी नहीं। आज की स्थिति आपके सामने है- रिकॉर्डतोड़ बेरोजगारी के कारण युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के खजाने भरती रही। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। मगर, सरकार टैक्स बढ़ाती गई। रेल हादसों और सड़कों, पुलों जैसे बुनियादी ढांचों के टूटने में सैकड़ों निर्दोष लोगों की असमय मृत्यु हुई। मगर सरकार ने जवाबदेही तक नहीं तय की।

(राहुल गांधी का 'एक्स' पर पोस्ट)

श्री स्वराज पॉल जी के निधन से दुःख हुआ, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्यमिता की भावना को पूरी लगन से आगे बढ़ाया। एक परोपकारी, राजनीतिज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित, वे ब्रिटेन में भारत के आजीवन मित्र रहे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ उनका जुड़ाव अमूल्य रहा है। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना।

(मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

एल. गणेशन : तमिलनाडु की एकता और अखंडता के लिए समर्पित

समर्पण के साथ-साथ जुझारू एवं अनुभवी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, पूर्व पत्रकार और मणिपुर व नागालैंड के पूर्व राज्यपाल एल. गणेशन का 15 अगस्त को चेन्नई में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शाम 6:23 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से तमिलनाडु के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में गहरा शून्य पैदा हो गया है, जहां उन्हें वैचारिक मतभेदों के बावजूद संबंध बनाने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जाना जाता था। मीडिया के प्रति दोस्ताना व्यवहार के कारण उन्हें प्यार से पत्रकार एलजी भी कहा जाता था। गणेशन का जीवन राष्ट्रवादी आदर्शों, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत राज्य में एकता को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता से पहचाना जाता था। 16 फरवरी 1945 को तंजावुर के मंदिर शहर में जन्मे गणेशन का पालन-पोषण एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरी जुड़ी हुई थीं। नौ साल की उम्र में अपने व्यवसायी पिता लक्ष्मी राघवन अय्यर को खोने के बाद उन्होंने अपनी एसएसएलसी की पढ़ाई पूरी की और राजस्व बंदोबस्त निरीक्षक के रूप में सरकारी नौकरी शुरू की। हालांकि, राष्ट्रवादी सिद्धांतों के प्रति उनके जुनून ने उन्हें नौ साल बाद इस्तीफा देकर पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक बनने के लिए प्रेरित किया। 1975 में आपातकाल के दौरान गणेशन ने तमिलनाडु के मुख्य आयोजक के रूप में कार्य किया और लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सक्रियतावाद मीनाक्षीपुरम में धार्मिक रूपांतरण, मंडैक्काडु में सांप्रदायिक अशांति और पुलियांगुडी व रामनाथपुरम में जाति संबंधी तनाव जैसी जटिल सामाजिक चुनौतियों को हल करने तक फैला था, जिससे उन्हें अपने सैद्धांतिक नेतृत्व के लिए व्यापक सम्मान मिला। 1991 में गणेशन तमिलनाडु में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी में शामिल हुए, एक ऐसा राज्य जहाँ पार्टी को पकड़ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें प्रमुख भूमिकाओं तक पहुंचाया, जिनमें संगठनात्मक सचिव, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और तमिलनाडु राज्य इकाई के अध्यक्ष शामिल हैं। भोपाल से राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने से पहले 18 महीने तक सांसद के रूप में कार्य किया। एक पूर्व पत्रकार होने के नाते गणेशन ने मीडिया के साथ बढ़िया तालमेल बनाए रखा, जिसकी पहचान उनकी सुलभता और स्पष्ट, ऑन रिकॉर्ड बयान देने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने भाजपा के तमिल मुखपत्र, ओरे नाडु का संपादन किया और पोत्तरमराई नामक एक पत्रिका की स्थापना की, जो दुनिया भर के तमिल विद्वानों, संगीतकारों और कलाकारों को पहचानने के लिए समर्पित थी, जो सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है। हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु और मलयालम में धाराप्रवाह, गणेशन एक प्रतिभाशाली वक्ता थे, जिनके देशभक्ति गीतों और राष्ट्रीय एकता पर दिए गए भाषणों का गहरा प्रभाव पड़ा। डीएमके, एआईएडीएमके और अन्य विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें तमिलनाडु के राजनीतिक क्षेत्र में अलग खड़ा कर दिया। यह वैचारिक सीमाओं से परे अपील, उनकी गर्मजोशी और कूटनीतिक कुशलता में निहित थी, जिसने उन्हें एक एकजुट करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रशंसा दिलाई। सहयोगी और विरोधी दोनों ही उनके सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की उनकी क्षमता को महत्व देते थे। अगस्त 2021 में गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने जुलाई से नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला और फरवरी 2023 से अपने निधन तक नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

सीमा का उल्लंघन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित कई राज्यों की पुलिस बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान उनकी भाषा बांग्ला से करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के चलते कुछ हास्यास्पद गलतियां हुई हैं। मसलन, दिल्ली पुलिस द्वारा बांग्लादेशी को एक भाषा के रूप में सूचीबद्ध करना भाषा विज्ञान के लिहाज से एक बड़ी छलांग है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में यह एक दुखद और हास्यास्पद प्रक्रिया बन गई है। दस्तावेजों में दर्ज की गई कई घटनाओं में भारतीय नागरिकों को सीमा पार बांग्लादेश में धकेल दिया गया है। इससे संबंधित परिवारों को काफी परेशानी हुई है और सरकार को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। राज्य सरकार या अदालतों के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को पश्चिम बंगाल में उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया गया है। संदिग्ध बांग्लादेशियों को वापस धकेलने की यह कवायद कानून की उचित प्रक्रिया, जो अक्सर लंबी और सख्त होती है, को दरकिनार करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। बांग्ला भाषियों को हिरासत में लिए जाने से पश्चिम बंगाल में एक बहस छिड़ गई है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने इसे बंगाली पहचान पर हमला करार दिया है और एक भाषाई आंदोलन छेड़ दिया है। बंगाली प्रवासियों को निशाना बनाए जाने का उनकी आजीविका पर तत्काल असर पड़ा है। हिरासत में लिए जाने और बांग्लादेश एक ऐसा देश, जिससे उनका शायद कोई रिश्ता न हो, में जबरन बसाए जाने के डर से पश्चिम बंगाल के कई प्रवासी कामगार अपनी नौकरियां छोड़ चुके हैं। एक खास मामले में दिल्ली पुलिस ने उन बंगाली भाषियों को हिरासत में लिया, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित एक प्रसिद्ध भूमि विनिमय संधि के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से, बांग्ला भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Trump focuses on peace, Europe on the pieces

Lawrence Freedman, emeritus professor of war studies at King's College London, has an acerbic description of the statecraft of US President Donald Trump: "Never assume you know what Donald Trump is going to do or say next because it is unlikely he does. Take seriously what he says at any time because that probably accurately reflects what he is thinking, but some of his thoughts can be very transitory and are soon replaced by others. If you don't like the positions being held on one day, push back because he might be convinced to hold a different position the next. Equally, when satisfied with today's position, do not assume it will last." Unsurprisingly, the representatives of Europe's ruling elite who headed to the White House to meet with Trump on Monday counted that there was scope to push back the consensus reached at the Alaska meeting between Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin on August 15 to the effect that achieving "a comprehensive, just, and sustainable resolution to the conflict surrounding Ukraine—including the eradication of its root causes" should be the priority, rather than an immediate ceasefire to end the war.

The European allies are alarmed that Trump dropped the idea of imposing crippling sanctions on Russia. But they feel excited that on the contentious issue of security guarantee for Ukraine, Trump extracted a "horosho" (okay) from Putin, which could open a pathway for inserting themselves into the Ukraine settlement process. The play here is to lock Trump into Europe and an anti-Russian Ukraine. Trump seemed to acquiesce when he told Fox News that American forces could assist Ukraine's allies in deterring future Russian attacks.

It will be extremely difficult for the present-day European leaders, whose rhetoric even today is replete with animus against Putin and Russia, to resume contacts directly with Putin. But on the other hand, the Europeans anyway have nothing concrete to propose constructively, either—apart from beating the dead horse of a ceasefire and piling even more sanctions on Russia and repeating the idea of a Western force to give security guarantee in a post-ceasefire politico-military scenario in Ukraine. In the final analysis, the Europeans' efforts narrow down to loosening the newfound bonding between Trump and Putin, which could make the Alaska matrix fluid and inchoate.How far these efforts will succeed time only can tell. But the interplay of these contradictions through the week since the Alaska meeting has made the overall "constructive and mutually respectful atmosphere" at Anchorage—to quote Putin—and his "friendly and trust-based conversation" with Trump less alluring and seemingly fragile.And then, there are the moving parts. Principally, the Russian offensive is sharply accelerating as it made it a point to launch the largest strike this month on Ukraine after Trump hosted Volodymyr Zelenskyy, and EU and UK leaders for talks. This is no small matter, since major sticking points of the peace talks are said to be potential land swaps and security guarantees for Ukraine. In the run-up to the Alaska meeting, Trump had threatened Russia with "severe consequences" if it did not accept a ceasefire, but afterwards, he summarily dropped that demand and said it was best to focus on a comprehensive peace deal, as Putin had pushed for. Again, Zelenskyy's European partners are not only supportive of a strong Ukrainian army that is provided with weapons and training by Western partners, but also are offering Ukraine a guarantee resembling Nato's collective defence mandate, Article 5, which stipulates that an attack on one member of the alliance is considered an attack on all.

Governance model of UTs needs a reset

The Union must act not as a jealous sovereign but as a generous trustee of UTs.

INDIA's constitutional tapestry is woven out of innumerable threads — threads of history and memory, of law and politics, of compromise and conviction — and one of its most peculiar yet enduring strands is the story of Union Territories (UTs), known at the time of constitutional inception as Chief Commissioner's provinces.The genesis of this constitutional conundrum traces back to the deliberations of the Constituent Assembly, where four members representing Chief Commissioner's provinces argued for their rightful place in India's democratic architecture.

KM Munshi, an active member of the Constituent Assembly, moved a resolution on April 30, 1947, for the formation of the Union Constitution Committee (UCC) and the Provincial Model Constitution Committee.

CM Poonacha (representing Coorg) proposed that a joint sub-committee of three members should specifically address the issues of the Chief Commissioner's provinces. His proposal was rejected; instead, the UCC assumed charge of the matter.The July 21, 1947, report of the UCC, recommended maintaining the status quo — that Chief Commissioner's provinces continue under Central governance in accordance with the Government of India Act of 1935. Yet, the debate was far from settled.

On July 30, 1947, Deshbandhu Gupta (representing Delhi) pressed for a special subcommittee to suggest "suitable constitutional changes to be brought in the administrative system of the Chief Commissioner's provinces". His amendment carried the day, and soon after the President of the Constituent Assembly, Rajendra Prasad, appointed a committee chaired by Pattabhi Sitaramayya.The Sitaramayya Committee's report, tabled in November 1948, offered a cautious blueprint. It proposed that Delhi, Ajmer-Merwara, Coorg and Panth-Piploda should be designated Lieutenant Governor's provinces with legislative assemblies and councils of ministers, though subject to overriding Union control. Andaman & Nicobar Islands, strategically sensitive, were to remain under direct Central authority. The report was path-breaking for its time, but tragically, it was never debated. The Drafting Committee quietly sidestepped it.Thereafter, the Assembly's discussions took a different turn. On November 9, 1948, MBL Bhargava, himself a member of the Sitaramayya panel, remarked that the curbs on autonomy it envisaged were accepted by representatives of these provinces only as an unwilling concession.The Drafting Committee, however, found itself perplexed, as Syed Muhammad Saadulla admitted. His defence of the committee's position articulated the prevailing hesitancy: how could small enclaves with a few lakh people sustain the apparatus of self-government? If Delhi with a population of 20 lakh was made a separate unit, how could Ajmer-Merwara (10 lakh) or Coorg (less than two lakh) be denied the

same? Mahavir Tyagi and Mohan Lal Gautam put it more bluntly in August 1949: these territories should remain under Central control temporarily and ultimately be merged with larger states.Thus, UTs came into being not by bold design but by default, an interim expedient, a "hanging fire" in the words of Poonacha. They were never meant to be permanent fixtures of the Republic. Yet history has its ironies. What the Constitution's framers considered too small, too fragile or too transitional have evolved today into robust communities with their own identities, issues and aspirations.The transformation is evident in hard numbers. Chandigarh's population now exceeds 15 lakh, surpassing Sikkim's six lakh and equalling Mizoram's figure. The case of Chandigarh is, however, unique. It was never an original UT or a Chief Commissioner's province. It was the capital of joint Punjab, built as a replacement for the loss of Lahore. When Punjab got trifurcated and the status of Chandigarh was contested, it became a UT as a consequence of Section 4 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, albeit for an interim period pending the settlement of its political question.

The combined population of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, according to the 2011 Census, stands at 5.85 lakh — merely 25,000 less than that of Sikkim. The Ministry of Health and Family Welfare's 2023 estimates indicate that Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, and Mizoram each have around 12 lakh residents. Puducherry's population of 16.46 lakh exceeds both Goa's and Arunachal Pradesh's 15 lakh. Delhi and J&K boast populations larger than those of several states.In terms of population density, the disparities are even more pronounced. Lakshadweep's density of 2,013 people per square km is twice that of Bihar, India's most densely populated state at 1,102. Puducherry's density of 2,598 is about 2.5 times Bihar's, while Chandigarh's 9,252 is more than eight times Bihar's figure. Delhi's staggering density exceeds 11,000 people per square km.These statistics demolish the argument that such territories are too small, too thinly populated or too peripheral to deserve democratic self-rule. If states with lesser populations and densities can sustain fully autonomous governments with legislative assemblies and councils of ministers, the continued denial of similar rights to UTs appears increasingly indefensible.

The political case is stronger still. Each UT has incubated its own political culture and policy problems — for instance, Chandigarh's land regimes, 'laal dora' questions, housing board legacies and lease-to-freehold transitions have been hanging fire for two-and-a-half decades.The solution to Chandigarh's problems lies in a representative and accountable governance model without prejudice to its status as a UT — since it is the capital of Punjab and Haryana — and the conflicting political claims of both states.This can be achieved by the people of the city electing a Mayor for a five-year term, who then would function through a Mayor in Council with powers over all subjects except land, police and public order that would be vested in the Administrator.

The latter would exercise these powers in statutory consultation with the Mayor in Council. It would be a directly elected, powerful Mayor — as most dynamic megapolises have around the world.For other UTs, the constitutional operating system remains stubbornly diarchic. In the three UTs with a legislature (Delhi, Puducherry and J&K), the Lieutenant Governor retains a wide berth, and the Union reserves public order, police, land and services. Delhi, as the capital, remains the theatre for tensions between local autonomy and national symbolism.

The gig economy has been in India since around 2010, when food delivery

With investigations at Dharmasthala on hold until the SIT gives its report, which could take months, the police could begin a parallel probe into the latest complaints

The Karnataka Assembly on Tuesday passed the Karnataka Platform-based Gig Workers (Social Security and Welfare) Bill to ensure a degree of security for those working on contract with digital platforms for delivering services. The bill provides a dispute resolution mechanism; establishes a gig workers' welfare board, which will set up a welfare fund; provides for registration of workers, aggregators or platforms; income security; and reasonable working conditions. These are essential covers for gig workers who have worked through a pandemic and continue to toil through regular extreme weather conditions to deliver goods while braving a range of threats from air pollution to traffic hazards.The timing of the bill's passage in Karnataka coincides with heavy rains and inundation in several parts of India—a steep challenge through which gig workers continue their work of delivering even when offices, schools and colleges are ordered shut for people's safety. Besides, gig workers also face challenges such as income instability, lack of paid

time off, and limited access to health insurance.

The gig economy has been in India since around 2010, when food delivery and ride-hailing platforms arrived. But a regulatory mechanism to ensure security for gig workers has remained conspicuous by its absence across India. So far, Rajasthan is the only state with a regulatory mechanism for gig workers with its Rajasthan Platform-based Gig Workers (Registration and Welfare) Act, 2023. The Karnataka Bill now has to pass through the legislative council to become an Act and benefit four lakh workers in the state.The gig economy has emerged as a key employment generator globally. According to Niti Aayog's estimates, India's gig sector had 77 lakh workers in 2020 and is expected to triple to 2.35 crore by 2029-30. The sector's growth has drastically shifted work practices over the last few years. It has led to new issues relating to employment, to which employers and business membership organisations have responded within a regulated framework in many countries. The regulatory landscape and various aspects of worker welfare in the gig economy are still nascent in India. The need of the hour is for institutions like business organisations to take up a greater role in shaping social dialogue and organising efforts to address the challenges faced by gig workers.

Financial fraud | Battling threats with AI-driven compliance

With the growth of digital transactions, frauds have also grown manifold—including those driven by AI tools. While the RBI and National Payments Corporation are deploying AI to detect and prevent threats, systemic compliance lapses can also be fixed with the help of AI to strengthen the system

India's digital payments landscape has witnessed exponential growth, with over 18,000 crore transactions recorded in 2024-25. UPI transactions alone surged by 137 percent to ?200 trillion in 2023-24.

However, this surge has been accompanied by a significant rise in digital financial frauds. Between April 2024 and January 2025, the country reported 24 lakh digital fraud incidents, amounting to losses of ?4,245 crore, a 67 percent increase from the previous year. High-value cyber fraud cases, involving sums exceeding ?1 lakh, have also escalated, with 29,082 such incidents causing losses of approximately ?175 crore.The rampant spike in financial frauds in India can be traced back to a range of contributing factors. One major driver has been the rapid shift to mobile-based and UPI platforms, which, while transformative, has outpaced user awareness and digital literacy. As a result, a large section of users remains highly susceptible to fake payment links, fraudulent apps and phishing attempts. At the same time, fraudsters are becoming more sophisticated, increasingly relying on AI-generated content, deepfakes and other advanced techniques to manipulate and mislead people.

But it's not just about individual vulnerabilities or evolving fraud tactics. Beneath the surface lies a deeper

issue: systemic compliance lapses. Weak enforcement of onboarding norms, gaps in merchant verification and inconsistent application of regulatory protocols are creating blind spots across the payments ecosystem.Addressing these structural flaws is just as important as strengthening frontline defences, especially if we hope to build a secure and resilient digital financial system. Against this backdrop, institutions are turning to artificial intelligence for proactive threat detection, automated incident response and adaptive risk modelling.Financial institutions and regulatory bodies are already turning to AI and machine learning (ML) technologies. The Reserve Bank of India has introduced MuleHunter.AI to detect and eliminate mule accounts, which are often instrumental in fraudulent financial schemes.

dditionally, the National Payments Corporation of India (NPCI) has launched a pilot project implementing a federated AI model in collaboration with leading banks to enhance fraud detection and risk assessment across the banking ecosystem. Mastercard's decision intelligence platform analyses 16,000 crore transactions annually, assigning risk scores in milliseconds to block unauthorised activity.

Some of the key roles of AI-driven models include threat detection and prevention through anomaly detection and behavioural analysis for recognising suspicious actions. With ML algorithms, AI models continuously monitor transactions and detect unusual activities. It also consists of automated incident response systems. With these systems, AI-based cybersecurity models can execute predefined responses by quickly recognising cyber incidents with AI-powered security orchestration, automation and response or SOAR systems. This incident response significantly minimises the damage before it escalates.Further, AI-powered endpoint security solutions and antivirus provide protection from phishing attacks. AI models continuously adapt to detect new and emerging threats, ensuring real-time protection. For instance, the RBI's AI/ML-based system has been designed to detect mule accounts that are used for phishing scams, enhancing accuracy and speed in detection and ultimately preventing fraudulent transactions.

Complementing these key elements can judiciously detect evolving threats. Natural language processing that can recognise phishing emails and malicious web links, and deep learning that can identify advanced persistent threats.RBI's MuleHunter.AI and NPCI's federated AI model trial signify a pivotal shift toward collaborative, data-driven security frameworks. Coupled with Indian Computer Emergency Response Team's mandated real-time incident reporting and RBI's exclusive '.bank.in' domain directive, these initiatives illustrate how AI can fill critical visibility gaps.However,

AI adoption faces a few key challenges. AI-generated threats aren't easy to spot even with advanced detection models. While the need for large datasets for training AI models raises privacy concerns, using limited data may lead to false positives by unfairly flagging legal activities or vice versa. There is also a growing risk of adversarial AI, wherein attackers can manipulate open AI models by feeding deceptive information.In the future, financial institutions must adopt strategies such as AI-driven zero trust architecture, an approach that demands rigorous verification of all users, systems and processes; with trust never assumed but consistently earned. Additionally, establishing a robust multi-stakeholder approach with integrated efforts spanning across regulators, financial institutions and technology providers would be crucial in ensuring that technological innovation is not undermined by vulnerabilities, and that trust in the financial system remains intact.

Wealthy Asian families bet big on crypto: Report

The growing interest comes as Bitcoin recently hit an all-time high of over $124,000. New rules, such as Hong Kong's stablecoin legislation and the United States' GENIUS Act, have further boosted confidence in the sector.

New Delhi.(Agency)

Wealthy Asian families and family offices are showing a growing appetite for cryptocurrency, making it a larger part of their investment portfolios. The move is being fuelled by record-breaking digital asset prices, easier access to trading platforms, and supportive rules in key markets, reported Reuters.Wealth managers across the region say interest has shifted sharply. A few years ago, investors only wanted a small slice of crypto. Now, many see it as an essential part of a modern portfolio. Demand has risen for not just Bitcoin, but also funds, exchange-traded products, and advanced trading strategies.Jason Huang, founder of Singapore-based NextGen Digital Venture, said his new crypto equity fund raised over $100 million in just a few months. "Our investors – mainly family offices and fintech entrepreneurs – see digital assets as an important diversifier," he explained. His earlier fund returned 375% in less than two years before closing last year.Global banks are also noticing the trend. UBS said some overseas Chinese family offices now plan to put around 5% of their portfolios into crypto. "Many second- and third-generation family members are taking active steps to understand and invest in virtual currencies," noted Lu Zijie, head of wealth management at UBS China.

The growing interest comes as Bitcoin recently hit an all-time high of over $124,000. New rules, such as Hong Kong's stablecoin legislation and the United States' GENIUS Act, have further boosted confidence in the sector.Crypto exchanges have been among the biggest winners. Hong Kong's HashKey Exchange reported an 85% jump in registered users over the past year. In South Korea, trading volumes at major exchanges have climbed more than 17% so far in 2025, with daily activity rising by over 20%.Experts believe the move reflects not just a hunt for high returns but also better risk control. Giselle Lai of Fidelity International said investors increasingly view Bitcoin as a hedge against global uncertainties due to its weak ties with stocks and bonds.

Singapore-based Revo Digital Family Office added that investors are becoming more sophisticated, moving from simple Bitcoin ETFs to directly holding tokens and exploring strategies like arbitrage.

As Saad Ahmed of crypto exchange Gemini put it: "The momentum has built because the asset class itself is maturing."

Apollo Hospitals' Suneetha Reddy sells 1.3% stake

CHENNAI.(Agency)

The Apollo Hospital Enterprise Ltd (AHEL) has officially announced on Friday that one of its promoters Suneetha Reddy has sold its 1.3% of stakes in the company through a block deal. Reddy will sell 1897239 equity shares at a price of Rs 7850 per share, a discount of 1% from Thursday closing at NSE.

In a Friday statement, the company said that the promoters' shareholding will be reduced from 29.3% to 28% after the deal. The pledged holdings of the promoter/promoter group (as a percentage of their total holding) will reduce from 13.1% from 2%, said the release. Reddy holds a 3.36% stake in the hospital, accounting for 48.34 lakh shares in the company, as per NSE dataThe proceeds will be used to pare down outstanding debt of the promoter group. Morgan Stanley India Company Private Limited acted as a selling broker to the sale.After the announcement, Apollo Hospitals share price fell by 0.11%, currently trading at Rs 7919 at 10.33 am.

Shares of the company touched its 52-week high of Rs 7,947 per share on Thursday.The company had reported a 42% rise in net profit from Rs 305 crore to Rs 433 crore in the first quarter of the current financial year. The company's operating also rose from Rs 675 crore Q1FY24 from Rs 852 crore in Q1FY25.

Earlier, Apollo Hospitals announced that it will partner with OneBanc, an AI-powered workplace banking and wellness platform. The aim is to enable new technology-enabled corporate health solutions.

Lord Swraj Paul, NRI industrialist and philanthropist, passes away at 93 in London

New Delhi.(Agency)

From the bylanes of Jalandhar to a regular name in the annual 'Sunday Times Rich List', Lord Swraj Paul, who died on Thursday evening in London, was one of the most well-known NRI entrepreneurs and philanthropists.Born to Pyare Lal, who ran a small foundry used to make steel goods, including buckets and other farming equipment, Lord Paul was exposed to business early in his life much before he went on to establish UK-based Caparo Group, a diversified businesses entity with interests predominantly in design, manufacture, marketing and distribution of value-added steel and niche engineering products.

Born on February 18, 1931, he completed high school education at Jalandhar and Bachelors in Science from Punjab University in 1949.Then he went to the US to pursue his Bachelors & Masters degrees in Mechanical Engineering from Massachusetts Institute of Technology (MIT).After completing his studies at MIT, he returned to India to join the family business, Apeejay Surrendra Group -- one of India's oldest business conglomerates.But as fate would have it, he relocated to the UK in 1966 in pursuit of treatment for his daughter Ambika who was suffering from leukemia.

Unfortunately, she died aged four.

Later, set up the Ambika Paul Foundation as a charitable trust that went on to donate millions to promote the wellbeing of children and young people all over the world through education and health initiatives.The Ambika Paul Children's Zoo in London is one of the major beneficiaries of the foundation.Lord Paul laid the foundation to set up Caparo in 1968 with headquarters in London and it went on to become one of the largest steel conversion and distribution businesses in the UK.Today, it has operations in the UK, India, the US, Canada, and the UAE with a turnover of over USD 1 billion.While he was blessed with success in business, his life had a fair share of tragedies.

GMR Airports board approves 5,000 crore fundraising, SPV for Delhi Cargo City project

CHENNAI.(Agency)

GMR Airports Ltd has approved plans to raise up to ?5,000 crore through a mix of instruments such as equity shares, non-convertible debentures (NCDs), warrants and foreign currency convertible bonds (FCCBs). The funds will be raised in tranches, depending on business requirements and market conditions.The board has also cleared the formation of a special purpose vehicle (SPV) for the Cargo City Project at Delhi's Indira Gandhi International Airport (IGIA), awarded by Delhi International Airport Ltd (DIAL). The Cargo City, spread across about 50 acres, will handle finance, design, development, operation and maintenance of cargo facilities, boosting the airport's logistics capacity.GMR operates major airports in Delhi, Hyderabad and Goa, and is also developing the Bhogapuram airport in Andhra Pradesh. In Nagpur, its subsidiary has secured a ?2,600 crore loan from Tata Capital for expansion, though final takeover awaits Union Cabinet approval.In FY25, GMR Airports handled 120.5 million passengers, up 9% year-on-year. Revenue for the year rose 18% to ?10,836 crore, while EBITDA grew 22.5% to ?4,188 crore. Despite strong growth, the company posted a net loss of ?817 crore for FY25, only slightly lower than the ?829 crore loss in FY24.

In the March quarter (Q4 FY25), revenue increased nearly 17% to ?2,977 crore and EBITDA rose 19% to ?1,123 crore. However, the net loss widened to ?253 crore compared with ?168 crore in the same quarter last year. Notably, GMR had turned profitable in Q3 FY25 with a ?202 crore net profit, supported by strong traffic and better margins.According to a leading infrastructure sector consultant, the fresh fundraising plan will give GMR greater financial flexibility to support expansion, strengthen its balance sheet and invest in large-scale projects such as the Cargo City.

ITR filing 2024–25: Comparing deductions under old and new tax regime

New Delhi.(Agency)

The deadline to file your Income Tax Return (ITR) for the financial year 2024–25 is September 15. With the date approaching, taxpayers need to know what deductions they can claim while filing. These benefits depend on whether you choose the old tax regime or the new one.While the new regime is simpler with lower tax rates, it offers only a handful of deductions. The old regime, on the other hand, allows a wider list of tax-saving options across investments, loans, insurance, and donations.

DEDUCTIONS UNDER THE NEW TAX REGIME

Even though the new tax regime limits deductions, you can still claim certain benefits.These include a deduction on the interest paid on a housing loan under income from house property, a deduction under Section 80CCD(2) for an employer's contribution to the central government pension scheme, and a deduction under Section 80CCH for contributions made to the Agnipath Scheme.

DEDUCTIONS UNDER THE OLD TAX REGIME

The old tax regime continues to offer a wide range of deductions that help taxpayers reduce their taxable income. These include deductions under Section 24(b) on interest paid for housing or home improvement loans. Under Section 80C, taxpayers can claim up to Rs 1.5 lakh for investments like PF, PPF, life insurance, and ELSS. There are further provisions under Sections 80CCC and 80CCD(1) for contributions to pension schemes.Employer contributions are also deductible under Section 80CCD(2). Other benefits include deductions for contributions to the Agnipath Scheme (80CCH), health insurance and preventive check-ups (80D), medical expenses for disabled dependents (80DD), and treatment of specified diseases (80DDB).

Students and families can benefit from Section 80E for education loans, while first-time homebuyers get relief under Sections 80EE and 80EEA. Loans for electric vehicles are covered under Section 80EEB.Donations to charities (80G), rural development or scientific research (80GGA), and political parties (80GGC) also qualify.

Rent payments without HRA can be claimed under Section 80GG. Senior citizens get deductions on interest income under Section 80TTA, while individuals with disabilities can claim under Section 80U.

Credit score confusion: Is CIBIL transparent enough in deciding your financial fate

New Delhi.(Agency)

Most people in India know the importance of a CIBIL. It can decide whether someone gets a car loan, a home loan, or even a credit card. Yet, very few actually know how CIBIL works or who controls it.The issue came up in Parliament recently when Karti P Chidambaram, Member of Parliament from Tamil Nadu, raised concerns about the lack of transparency in how CIBIL functions."If you want to take a car loan, if the finance minister of this country wants to take a house loan, everything depends on the CIBIL score. But nobody knows how this CIBIL organisation works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal," Chidambaram said in Parliament.He added that many borrowers

face problems when their repayments are not reflected properly."There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all. Every time we go to a bank, we are told our score is bad. Farmers repay loans using subsidies, but CIBIL does not update it. If there is a settlement with an ARC, CIBIL does not update it. There must be greater transparency," he said.His comments have drawn attention to how exactly CIBIL functions and why it plays such a big role in everyday finances.

WHAT IS CIBIL?

CIBIL, or TransUnion CIBIL, is one of four major credit bureaus in India. The others are Equifax, Experian, and CRIF High Mark. All these bureaus are private companies, but they are regulated by the Reserve Bank of India (RBI) under the Credit Information Companies (Regulation) Act.

UPI providers may revise business model as subsidy cuts raise concerns over costs

CHENNAI.(Agency)

Every time you scan a payment QR code and the payment is completed – it appears seamless, free of cost. But is the transaction actually free? While the unified payments interface (UPI) transactions remain free for users, the government bears the cost for maintaining the payment infrastructure behind the service by subsidising banks and other stakeholders, especially in case of small value transactions.

However, consecutive reductions in government subsidies and signs of further lowering it have put pressure on UPI providers, with industry experts indicating that a change in their business model may be imminent, particularly as the cost of running low-value transactions becomes a growing concern.While the industry has raised concerns, financial sector experts—including some within the government—point out that the subsidy was introduced with temporary objectives, such as encouraging digital transactions during demonetisation and the Covid pandemic. They argue that expecting public money to permanently sustain private businesses is not a fair demand. More importantly, the core technology infrastructure for UPI payments was built by the government, and private players are already leveraging it for their business without making any significant investment of their own.The finance ministry has reduced the incentive for processing small-value UPI payments at small merchant outlets to 0.15% per transaction from 0.25% previous year. This means that when banks earlier got an incentive of Rs 0.25 for a transaction of Rs 100, they'll now get only Rs 0.15 for the same transaction.In its budgetary allocation, the government reduced its incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (Person to Merchant – P2M) for the financial year 2024-25. The incentive was more than halved to Rs 1,500 crores from Rs 3,500 crores in the previous year. However, the incentive payout by the Government was actually Rs 3,631 crores last year.Further, the Reserve Bank of India governor Sanjay Malhotra recently hinted that the free lunch is soon to be finished. "Any important infrastructure must bear fruit," he said in the Financial Express BFSI event in Mumbai recently. He added that for any service to be truly sustainable, "its cost should be paid whether collectively or by the user."The incentive exclusively covers UPI P2M transactions of up to Rs 2,000, specifically targeting small merchants to encourage the adoption of digital payments at the grassroots level.

Real-money gaming ban rocks advertising, sports sponsorships: What's at stake

Sebi would also work with the corporate affairs ministry and stock exchanges to build a regulated platform for pre-IPO or unlisted companies so that they can trade with required disclosures.

MUMBAI.(Agency)

For over a decade, real-money gaming and fantasy sports quietly rewrote the rules of India's advertising and sports sponsorship landscape. Platforms like Dream11, MPL, and My11Circle started small, but soon turned cricket into a multi-crore playground for advertisers.From flashy IPL campaigns to celebrity endorsements, the rise of fantasy sports created a new ecosystem where brands, broadcasters, and even grassroots leagues thrived.Now, with Parliament passing the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, which bans all money-based online games, that ecosystem has been thrown into sudden turbulence.Advertisers, sports bodies, and content creators are left staring at empty budgets and uncertain strategies.

THE RISE AND THE SUDDEN HALT

India boasts 568 million active gamers, roughly one in every five globally. The online gaming market has grown to $3.7 billion, with the real-money segment—fantasy sports, rummy, poker—accounting for 86% of industry revenues.Fantasy sports platforms were some of the largest spenders in sports advertising. Dream11 alone reportedly holds Rs 350 crore in cricket sponsorship deals, while My11Circle commands IPL fantasy rights worth Rs 625 crore over five years.Together, their spending helped push the Indian sports ad market to Rs 16,600 crore in 2024, with cricket at its heart.The new legislation disrupts this flow almost overnight. Analysts estimate that real-money gaming contributes over Rs 4,500 crore annually to advertising in India.Broadcasters, ad agencies, and influencers now face a sudden void—plans frozen, campaigns delayed, and revenue streams blocked."A number of major sporting events and teams,

including cricket, are sponsored by companies whose business may now fall within the ambit of 'online money games'.

These include fantasy draft games, in particular, as well as games such as rummy and poker," said Vikram Jeet Singh, Partner at BTG Advaya."The conduct of these games will be made illegal, and even the promotion and advertising of such games may attract penalty. Broadcasters cannot, for example, show ads during sporting events that promote online money games. Online content curators such as YouTube will be barred from showing these ads, as well," he added.

MORE THAN JUST MONEY

The implications go deeper than balance sheets. Fantasy sports sponsorships became an engine not just for advertising, but for sports development itself.Smaller leagues, emerging sports, and grassroots talent often relied on this indirect support. With those lifelines threatened, India's sporting pipeline may face long-term consequences.Digital content creators and marketers who catered to gaming audiences are also feeling the pinch. Reduced budgets ripple across influencer collaborations, content production, and esports events linked to real-money platforms."Yes, a number of sports teams and events are sponsored by companies involved in offering online money games. For some entities, online money games may account for the majority of their revenues.

Street dogs case: Who's emerged victorious after Supreme Court's verdict?

►In the street dog case, the Supreme Court's verdict sees elements of both sides of the stray dog arguments: strays will be sterilised and vaccinated, aggressive ones will be kept in shelters, and public feeding will be limited to designated areas. But which side really won the stray dog debate?

Agency New Delhi.

More than the stray dogs, it was the debate that came across as rabid. As with most issues these days, no side, neither the activists nor those opposing strays on Delhi's streets, seemed to have an iota of flexibility. The ruling by the Supreme Court in the matter was seen as another extreme. However, the Supreme Court verdict on Friday is a victory of reason and balance.The bench of Justices JB Pardiwala and R Mahadevan on August 8 ordered civic bodies in Delhi NCR that all stray dogs be rounded up, sterilised and kept in shelters within eight weeks.

On 28 July, the Bench of Justices Pardiwala and Mahadevan took suo moto cognisance of a news report in The Times of India's Delhi edition, titled 'City Hounded by Strays, Kids Pay Price'. The Bench noted that the news item contained "very disturbing and alarming" figures and facts.

It is a fact that Delhi NCR has seen a surge in dog bite and rabies cases, which is due to ineffective policy implementation by civic bodies, including the Municipal Corporation of Delhi (MCD).

To ensure humane and effective dog population management, the central government framed the Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023, under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. However, there was total failure in the implementation of the ABC rules on the ground.

8 LAKH STRAYS IN NCR AND 25,000 DOG BITE CASES IN NCR

Delhi NCR saw a steep rise in the street dog population and a corresponding increase in attacks by strays. It was against this background that the Supreme Court took

up the case and delivered the judgment.

Delhi has around 8 lakh street dogs and witnessed around 25,000 dog bite cases in 2024 and over 3,000 in January 2025 alone.The August 8 order by the two-judge Supreme Court bench caused massive uproar and petitions by street dog lovers and activists were filed in the apex court.

Animal activists and dog feeders took to the streets and reams after reams were written slamming the order. The other side also saw people seeking the other extreme of getting dogs permanently removed, though they were outnumbered. The majority, it was said, silently backed the move to control the stray dogs.

PEOPLE HAIL THE VERDICT AND ITS MIDDLE PATH

On Friday, a three-judge bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and NV Anjaria on Friday ordered modifications to the August 8 verdict.Instead of herding street dogs in shelters as directed earlier, the new order asks them to be sterilised and returned to the streets. Only dogs that are aggressive should be kept in shelters, the SC said on Friday."A victory for compassion, coexistence and justice," wrote software engineer and animal activist Divesh Sharma on X.

Some dog lovers framed it as a victory."We have Won," wrote New Delhi-based social entrepreneur Harteerath Singh Ahluwalia on X.

Caught on CCTV: Bihar man beaten with sticks 100 metres from police station

Agency New Delhi.

A shocking video from Bihar's Nawada district has surfaced online, showing a group of men brutally beating a young man in broad daylight. The incident took place on August 17 near an under-construction cement factory, barely 100 meters from the Warisaliganj police station.The victim has been identified as 26-year-old Manish Kumar, a resident of Baso Chak village under the Warisaliganj police station area.

In the viral video, several men are seen chasing Manish and attacking him with sticks. Even after he falls to the ground, the assailants continue to beat him, while bystanders look on and record the incident without intervening.Manish was rushed to a local hospital by his family and later referred to Pawapuri VIMS for further treatment due to the severity of his injuries.

His father, Ramadhin Prasad Yadav, has filed a formal complaint at the Warisaliganj police station, naming four individuals from Chainpura village.

He alleged that the accused and their accomplices attacked his son without any provocation and also looted a gold chain and Rs 5,000 in cash during the assault.Police have registered a case and launched an investigation.

Chaos At First Event By Delhi Chief Minister After Attack, Man Escorted Out

Agency New Delhi.

Chaos erupted at an event attended by Delhi Chief Minister Rekha Gupta this morning, leading to security concerns at her first public event since being attacked at a grievance redressal programme at her residence two days ago. A man raised slogans at the event in Delhi's Gandhinagar, apparently after an argument with local traders at the wholesale garment market, and was immediately removed from the venue by the police.The man initially raised slogans in support of the Chief Minister, followed by a "murdabad" slogan against someone else, which alerted the police. As cops swung into action and escorted the man out, he claimed he was a BJP worker, which is yet to be verified.

The police are yet to release an official statement on this incident.Ms Gupta continued with her speech thereafter at the inaugural event of Vastrika, an open market garment show at the Gandhi Nagar wholesale market. Speaking in the 'Yamunapaar' area (near the Yamuna's banks), she reiterated her vow to clean the Yamuna River and work without pause.

"Mother Yamuna will start appearing better and more beautiful with time. There will be water lines and sewer lines across Yamunapar. Water pipelines will be laid, and multiple parking lots and toilets will be built. I assure you that your Chief Minister Didi will not be afraid, will not get tired, will not lose. Till Delhi gets its rights, she will keep fighting with you. It is my vow to continuously fight with you," she said.

Gandhinagar MLA Arvind Singh Lovely was also present at the event.This comes amid heightened security in view of Wednesday's attack on Ms Gupta. The Chief Minister was listening to public grievances when she was attacked by a man in his 40s, identified as Rajesh Sakriya from Gujarat. The attacker's mother later claimed he was upset over the Supreme Court's order to move all stray dogs to shelters.

Thunderstorms and rain expected over weekend in Delhi

Agency New Delhi.

Thunderstorms and lightning are likely to hit the capital over the weekend, with the India Meteorological Department issuing a yellow alert for Saturday.

Delhiites can also expect wet weather in the coming days, with forecasts suggesting cloudy skies and light to moderate rainfall across the city and adjoining NCR.

On Friday, isolated places in Delhi may witness very light to light rain or thundershowers by late evening, with the wet spell expected to continue through next week.The intensity of showers is likely to increase from Saturday, August 23, with one or two spells of light to moderate rain at most places, along with the

possibility of intense downpours at isolated locations. Similar conditions are forecast for Sunday.

On Monday, August 25, light to moderate rain and thundershowers are predicted across the capital, while August 26 and 27 may see very light to light showers under generally cloudy skies.The Safdarjung observatory, considered Delhi's base weather station, recorded a maximum temperature of 34.8°C and a minimum of 25.9°C, both close to normal.

What are you doing? Top court raps parties' 'inaction' over missing Bihar voters

The Supreme Court's remarks came after the Election Commission said none of the major political parties in Bihar filed any objections over the draft electoral rolls.

Agency New Delhi.

The Supreme Court on Friday pulled up the political parties in Bihar over their inaction in assisting the people who were left out of the draft electoral rolls during the special intensive revision (SIR) in filing claims and objections.

A two-judge bench headed by Justice Surya Kant directed 12 political parties to issue orders to party workers to assist people in filing their complaints with any of the 11 documents listed by the Election Commission or Aadhaar card. The court also said it was not altering the timeline of the exercise for now.

In its previous hearing, the Supreme Court said those whose names have been struck off the draft list could submit their Aadhaar cards to challenge this deletion.

"All 12 political parties in Bihar shall issue specific directions to party workers to assist people in filing and submission of requisite forms with any 11 documents in Form 6 or Aadhaar card," Justice Kant said.

'POLITICAL PARTIES MUST ASSIST VOTERS'

The top court expressed surprise after the poll body said Bihar had over 1.68 lakh booth-level agents (BLAs) of political parties, but only two objections have been filed so far.

This despite vehement criticism by the opposition, which has claimed that the SIR exercise would disenfranchise lakhs of voters. Around 65 lakh voters have been dropped from the draft electoral rolls published by the ECI on August 1.Several opposition parties have claimed large-scale irregularities in the numbers, claiming several of those who are alive were declared dead in the draft rolls."We are only surprised by the inaction of political parties. After appointing BLAs (booth-level agents), what are they doing? Why is there a distance between people and local political persons? Political parties must assist voters," the court said in pointed remarks.

"BLAs of all political parties are to check whether the 65 lakh who are not included in the draft roll are facilitated or are dead or have voluntarily shifted their residence," the court further said.

Order on pharmacies as Ayushman health facilities irks chemists

Agency New Delhi.

The State Health Agency's order directing pharmacies to mandatorily register as health facilities under the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) has triggered sharp opposition from chemists, who have taken up the matter with the CM.

They have questioned the legality of the directive and demanded that enrolment remain voluntary unless backed by law. The Drugs Control Department issued an order on Thursday asking all pharmacies to register themselves on the Health Facility Registry (HFR), describing it as a "key building block" of the ABDM.

"Being an integral part of the healthcare system, you are requested to sensitise members of your associations and other chemists to get enrolled under the HFR of the ABDM portal," the order stated.Pharmacy associations, however, argue that chemists are already governed by the Drugs and Cosmetics Act, 1940, and the Pharmacy Act, 1948, and any additional compliance requirement must follow due process.

In a letter to the CM, the Retail Distribution Chemist Alliance (RDCA) said, "While RDCA supports the digital health mission and recognises its long-term benefits, we submit that there is no provision in the Drugs and Cosmetics Act or the Pharmacy Act mandating such enrolment. Licensed chemists are already fully regulated under existing laws. Additional compliance can only be imposed through a proper legal notification or amendment, not through an administrative letter." The association alleged that no stakeholder consultation, awareness drive, or training session was conducted before the directive was issued. It also pointed out that hospitals, clinics, doctors, e-pharmacies and food delivery platforms selling medicines have not been subjected to similar directions, calling the move "discriminatory and unfair."

Novo Nordisk insulin and weight loss injections stolen in transit, alert issued

Agency New Delhi.

The Central Drugs Standard Control Organization on Thursday issued a health alert in response to the theft of multiple batches of Danish pharmaceutical company Novo Nordisk's insulin and Wegovy injections, popular medication for weight loss.According to the notice, the batches were stolen during transit from its Bhiwandi hub to various distribution routes. It also added that the stolen batches included insulin doses marketed as Ryzodeg FlexTouch and Fiasp (Penfill and FlexTouch) and three Wegovy doses (0.25 mg, 0.5 mg and 1 mg).These batches were en route to locations such as Nagpur, Raipur, Cuttack and Kolkata. The theft is currently under police investigation.

The regulator in its health alert letter mentioned that these stolen drugs are rDNA injectables that require strict temperature control. Any mishandling or improper storage could affect product quality and endanger patient safety.

"The products under consideration are rDNA origin injectables which are required to be stored at 2-8 degrees Celsius.

The quality of the products may be compromised if the products are not handled in proper storage conditions since the formulations are supposed to be maintained at 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius failing, which would impact the quality of the product and in turn impact the safety of the patients," the health alert letter read.

In response, the regulator has instructed state drug controllers to closely monitor the distribution of these products and enforce action under the Drugs & Cosmetics Act, 1940.

Healthcare providers have been urged to guide patients to report any adverse effects and ensure medicines are sourced only from authorised suppliers with valid documentation.

"To be careful and procure the above products from authorized sources only and with proper invoice," the letter added.

It may be noted that while Novo Nordisk's insulin brands are well-established in India, Wegovy, which is a popular medication for weight loss, was introduced in the Indian pharma market in the late June only.

"ISRO Really Helped": Shubhanshu Shukla On Rocket Oxygen Leak Before Space Mission

Group Captain Shubhanshu Shukla was originally planned for lift-off on May 29, but his mission was postponed due to multiple delays.

Agency New Delhi.

Indian astronaut Group Captain Shubhanshu Shukla on Thursday said ISRO engineers "really helped" by flagging the liquid oxygen leak in the Falcon-9 rocket that launched his Axiom-4 mission to the International Space Station (ISS) in June.

Asked by during a press conference in Delhi on how he "thanked" ISRO chairman V Narayanan and his team for "saving his life", Group Captain Shukla said everybody doing human space flight missions is "very responsible""It is important because lives are involved, and if somebody makes a mistake, people do lose lives," Group Captain Shukla, the first Indian astronaut to travel to the ISS, said."It really helped for the technical experts from ISRO to be available there and to have those important discussions," he said while addressing a press conference along with Mr Narayanan, backup astronaut for Axiom-4 mission Prashanth Balakrishnan Nair, and Union Minister Jitendra Singh.

Group Captain Shukla was originally planned for lift-off on May 29, but his mission was postponed to June 8 as SpaceX's Dragon spacecraft was not fully ready. The mission was then postponed due to high winds in the ascent path of the Falcon-9.

The launch was delayed again due to a liquid oxygen leak in the rocket, and the fault was observed following a demand for due diligence from the ISRO Chairman. was the first media channel to report on ISRO's involvement.

He then flew to the space station on June 25 alongside former NASA astronaut Peggy Whitson, Poland's Slawosz Uznanski-Wisniewski, and Hungary's Tibor Kapu. They returned to Earth on July 15.

"SpaceX Lightly Handled Rocket Leak, Could've Been Fatal": ISRO Chief

ISRO chairman V Narayanan said SpaceX had probably taken "lightly" the liquid oxygen leak in the Falcon-9 rocket, putting at risk the lives of the four astronauts.Addressing a press conference with Group Captain Shukla, Mr Narayanan said it was at the insistence of ISRO engineers that SpaceX examined the leak detected in the oxidiser lines that carry liquid oxygen to the rocket engines and discovered a crack that could have proved fatal.

"If with the crack the rocket lifts off, with the vibrations, it will give way the moment it lifts off. Once it gives way, it is a catastrophic situation, nothing else," he said.

"To their (SpaceX's) surprise, it was a crack. Finally, everything had to be corrected. Probably, they took it a little lightly," he said.

He said the ISRO team, which has worked on liquid oxygen-powered engines for over 40 years, insisted on a complete correction, which was carried out by the SpaceX team."But for the complete correction, it would have ended in a catastrophic situation. We have saved the lives of four astronauts," Mr Narayanan said.

NEWS BOX

7.5 magnitude earthquake rattles Chilean Antarctic region, no tsunami threat

SANTIAGO. (Agency)

A 7.5 magnitude earthquake rattled the Chilean Antarctic region and the southern Drake Passage on Thursday, the US Geological Survey said.

There was no threat of a tsunami from the quake, which took place at 10:16 pm (0216 GMT Friday), at a depth of 6.7 miles (10.8 kilometers), the survey said in a statement.Drake Passage is a turbulent, 500-mile-wide strait between South America and Antarctica, connecting the Atlantic and Pacific Oceans.

The National Tsunami Warning Center confirmed that a tsunami was not expected.Chile's national disaster response service (Senapred) described the earthquake as "medium intensity" and said a "precautionary alert" had been issued for the Antarctic territory.A source from the Chilean interior ministry said "there is no danger for the Magallanes region," the southernmost inhabited area of the South American continent.The state of precaution "requires abandoning beach areas" and "rocky shores" of the national Antarctic territory, according to Senapred.

Israel to mobilize 60,000 reservists ahead of an expanded Gaza City operation

BANGKOK.(Agency)

Thailand's billionaire Shinawatra dynasty has dominated the kingdom's politics for 25 years, despite coups and court cases including Friday's lese-majeste acquittal of its patriarch.A Bangkok court cleared 76-year-old Thaksin Shinawatra of breaching Thailand's tough royal insult laws in an interview with South Korean media a decade ago.AFP looks at the Shinawatra family's turbulent quarter-century of dominating Thai politics and battling the kingdom's traditional conservative elite.

Founding father

Thaksin served as a police officer before making his fortune in telecoms and launching the Thai Rak Thai (Thais Love Thais) party, promising to use his business savvy to uplift the rural poor.

His populist policies won the devotion of countryside voters but the ire of the pro-monarchy, pro-military establishment that regarded him as an insurgent threat to the traditional social order.He became premier in 2001 and was the first democratically elected Thai prime minister to serve a full term.He was then re-elected in a landslide by voters grateful for cash injections amid the Asian financial crisis, leading the first Thai party ever to secure an overall majority alone.However, Thaksin was dogged by corruption allegations and months of protests. Tanks rolled into Bangkok while he was on an overseas trip in September 2006 and the military toppled his government.He purchased Manchester City despite his Thai assets being frozen the following year, and later sold the British football club for a sizeable profit.

Thaksin took himself into exile in 2008 but never stopped commenting on national affairs -- or, according to his critics, meddling in them.

A family affair

Thai Rak Thai was dissolved after the 2006 coup, but its successor, the People's Power party, won the next election. Thaksin's brother-in-law Somchai Wongsawat was briefly prime minister in 2008 before the courts ordered that People's Power be dismantled, too.

UN says workers' health 'severely impacted' by rising heat

GENEVA . (Agency)

Rising global temperatures are having an ever-worsening impact on the health and productivity of workers, the United Nations said Friday, urging immediate action to tackle the dangers of heat stress.

Extreme heat is posing growing challenges in the workplace, the UN's health and climate agencies said, as they issued guidance for governments, employers and health authorities to mitigate the risks.

"Immediate action is needed to address the worsening impact of heat stress on workers worldwide," they said.Many workers are regularly exposed to dangerous heat conditions, the World Health Organization and the World Meteorological Organization said.But the WHO and WMO said the frequency and intensity of those extreme heat events had risen sharply, increasing the risks for both outdoor and indoor workers alike.Manual workers in sectors such as agriculture, construction and fisheries are particularly hard hit, they said in a report.The agencies said worker productivity dropped by two to three percent for every degree above 20C.The related health risks include heatstroke, dehydration, kidney dysfunction, and neurological disorders.

Economic Factor

"Occupational heat stress has become a global societal challenge, which is no longer confined to countries located close to the Equator," said WMO Deputy Secretary-General Ko Barrett."Protection of workers from extreme heat is not just a health imperative but an economic necessity."The agencies called for occupational heat action plans, tailored to specific industries and regions.The guidance drew on findings by the UN's International Labour Organization (ILO), highlighting that more than 2.4 billion workers are exposed to excessive heat globally -- 71 percent of the world's working population.It results in more than 22.85 million occupational injuries each year and almost 19,000 fatalities."Investing in effective, preventive and protective strategies would save the world several billion dollars every single year," said Joaquim Pintado Nunes, the ILO's chief of occupational safety and health and the working environment.

Immediate action needed to address worsening impact of heat stress on workers worldwide: UN

Manual workers in sectors such as agriculture, construction and fisheries are particularly hard hit.

GENEVA .(Agency)

Rising global temperatures are having an ever-worsening impact on the health and productivity of workers, the United Nations said Friday, urging immediate action to tackle the dangers of heat stress.

Extreme heat is posing growing challenges in the workplace, the UN's health and climate agencies said, as they issued guidance for governments, employers and health authorities to mitigate the risks."Immediate action is needed to address the worsening impact of heat stress on workers worldwide," they said.Many workers are regularly exposed to dangerous heat conditions, the World Health Organization and the World Meteorological Organization said.But the WHO and WMO said the frequency and intensity of those extreme heat events had risen sharply, increasing the risks for both outdoor and indoor workers alike.Manual workers in sectors such as agriculture, construction and fisheries are particularly hard hit, they said in a report.The agencies said worker productivity dropped by two to three percent for every degree above 20C.The related health risks include heatstroke, dehydration, kidney dysfunction, and neurological disorders.

Economic factor"Occupational heat stress has become a global societal challenge, which is no longer confined to countries located close to the Equator," said WMO Deputy Secretary-General Ko Barrett."Protection of workers from extreme heat is not just a health imperative but an economic necessity."The agencies called for occupational heat action plans, tailored to specific industries and regions.

The guidance drew on findings by the UN's International Labour Organization (ILO), highlighting that more than 2.4 billion workers are exposed to excessive heat globally -- 71 percent of the world's working population.It results in more than 22.85 million occupational injuries each year and almost 19,000 fatalities.

"Investing in effective, preventive and protective strategies would save the world several billion dollars every single year," said Joaquim Pintado Nunes, the ILO's chief of occupational safety and health and the working environment."Without bold, coordinated action, heat stress will become one of the most devastating occupational hazards of our time, leading to a significant loss of life and productivity."

Adapt or die

The guidance called for a focus on middle-aged and older workers, and those with chronic health conditions or lower physical fitness who would be more susceptible to heat stress.It said workers, trade unions, health experts and local authorities should work together to come up with heat-health strategies that would then be widely supported.It said heat stress symptoms were often misdiagnosed, with people failing to recognise the signs.The last WHO technical report and guidance on workplace heat stress dates from 1969, "when the world looked very different in terms of climate change", said the WHO's environment chief Ruediger Krech.

"What's changed is the severity," he said, with each of the past 10 years being in the warmest 10 ever recorded.WMO services division senior director Johan Stander added: "We must face up to the future of extreme heat. It's a reality for many: a case of adapt or die."

Kenyan hunter-gatherer community, Ogiek, fights for rights following eviction from forest

NAROK. (Agency)

Fred Ngusilo stoops to pick up a leather pouch, once used to collect honey, and a discarded shoe from the Mau forest floor, painful reminders that his Ogiek hunter-gatherer community once quietly flourished in southern Kenya, before they were evicted and their homes destroyed.Ngusilo belongs to the Ogiek group, which is among the last hunter-gatherer communities in Africa and one of the most marginalised in Kenya.He described how their ancestral lands were seized by the government in the name of conservation at the end of 2023, when men armed with hammers and axes suddenly appeared, violently evicting them from their homes."When I come here, I feel that I'm so sad. Tears are coming out of my eyes," Ngusilo said, his eyes resting on the remains of his father and grandfather's house.Behind the 38-year-old human rights activist, bees buzz, and some of his community peacefully weave their cattle through the trees -- despite a ban on livestock, brutally enforced by Kenyan Forestry Service (KFS) rangers.In December, a herder drowned while fleeing from the rangers, Ngusilo said.The calm of the Mau Forest contrasts with stories of decades of persecution and

dispossession recounted by its indigenous people -- all in the name of conservation.The African Court on Human and Peoples' Rights (AfCHPR) ruled in 2017 and 2022 that the evictions were illegal, ordering Nairobi to pay reparations equivalent to more than $1 million and to recognise their ancestral lands.

But Kenya has still not complied.

'We are suffering greatly'

Deprived of their livelihoods, they recount a difficult daily existence that is slowly but surely destroying their traditions and their language.

"Before, in the forest, we could survive -- eat honey, hunt, live," Ngusilo's grandmother, Janet Sumpet Ngusilo, 87, said."Now, out here, we are suffering greatly."

At a festival earlier this month, hundreds of community members rallied to keep the ceremonies and traditional songs alive, but also to remember what they have lost."I survived on meat and honey. Young people today don't know that life," said Salaton Nadumwangop, describing how he would sleep beneath the trees.

"The forest is our life," the 55-year-old Nadumwangop, dressed in traditional costume and a fur hat pinned with beads evoking bees, told AFP.

Existential threat

A government representative at the festival, Josphat Lodeya, promised the verdicts of the AfCHPR court would be implemented

US halts work visas for foreign truck drivers

CHANDIGARH..(Agency)

The United States has decided to stop issuing work visas for commercial truck drivers after a deadly crash, involving an Indian driver staying illegally in the country, drew national attention. This move which might impact Indian drivers who were hoping to work in the US transportation industry.Announcing this move, US Secretary of State Marco Rubio wrote on X, `` Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers. The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on US roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers.''A few days back a Punjabi-origin truck driver was charged with killing three people on a highway in Turnpike of Florida, while making an illegal U-turn and collided with a passenger van.

According to Transportation Secretary Sean Duffy,

Harjinder Singh, who is from India, allegedly entered the United States illegally from Mexico and failed an English examination after the crash.

The police said he attempted to make an illegal U-turn through an "Official Use Only" access point blocking traffic and causing the fatal crash that resulted in the deaths of three people.Federal Motor Carrier Safety Administration has launched an investigation into a crash that killed three people.

In April, US President Donald Trump signed an executive order mandating that commercial truck drivers in the US are proficient in Englsih.

Recently, US Citizenship and Immigration Services also wrote on X,`` Protecting the integrity of our lawful immigration system to make America safe again is our top priority. We've restored our robust screening and vetting capabilities so we can detect aliens with harmful intent and deter them from trying to enter the U.S. Immigration fraud is a crime we take seriously. Aliens who use false information or deceitful practices to unfairly obtain immigration advantages will face serious consequences.''

Former Thai PM Thaksin Shinawatra says he has been acquitted of royal defamation

Thaksin's opponents, who were generally staunch royalists, accused him of corruption, abuse of power and disrespecting then-King Bhumibol Adulyadej, who died in 2016.

BANGKOK . (Agency)

Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra said he was acquitted of royal defamation by a court Friday.His lawyer also confirmed the verdict, but the Bangkok Criminal Court did not immediately issue a statement.The law on defaming the monarchy, an offense known as lese majeste, is punishable by three to 15 years in prison. It is among the harshest such laws globally and increasingly has been used in Thailand to punish government critics.When he was indicted last year, Thaksin's freedom on bail was approved with a bond of

500,000 baht ($13,000) with the condition that he could not travel out of Thailand unless approved by court. His passport was confiscated.Thaksin's opponents, who were generally staunch royalists, accused him of corruption, abuse of power and disrespecting then-King Bhumibol Adulyadej, who died in 2016.

Thaksin was originally charged over remarks he made a year earlier to journalists in South Korea. The case was not pursued at that time because he was in exile and the necessary legal procedures could not be completed.

Since his return, Thaksin has maintained a high profile, traveling the country making public appearances and political observations that could upset the powerful conservative establishment that was behind his 2006 ouster.

China on a race to build world's largest solar farm to meet emissions targets

TALATAN . (Agency)

Chinese government officials last month showed off what they say will be the world's largest solar farm when completed high on a Tibetan plateau. It will cover 610 square kilometers (235 square miles), which is the size of Chicago.China has been installing solar panels far faster than anywhere else in the world, and the investment is starting to pay off. A study released Thursday found that the country's carbon emissions edged down 1% in the first six months of 2025 compared to a year earlier, extending a trend that began in March 2024.The good news is China's carbon emissions may have peaked well ahead of a government target of doing so before 2030. But China, the world's biggest emitter of greenhouse gases, will need to bring them down much more sharply to play its part in slowing global climate change.For China to reach its declared goal of carbon neutrality by 2060, emissions would need to fall 3% on average over the next 35 years, said Lauri Myllyvirta, the Finland-based author of the study and lead analyst at the Centre for Research on Energy and Clean Air."China needs to get to that 3% territory as soon as possible," he said.

'Moment of global significance'

China's emissions have fallen before during economic slowdowns. What's different this time is electricity demand is growing — up 3.7% in the first half of this year — but the increase in power from solar, wind and nuclear has easily outpaced that, according to Myllyvirta, who analyzes the most recent data in a study published on the U.K.-based Carbon Brief website.

"We're talking really for the first time about a structural declining trend in China's emissions," he said.China installed 212 gigawatts of solar capacity in the first six months of the year, more than America's entire capacity of 178 gigawatts as of the end of 2024, the study said. Electricity from solar has overtaken hydropower in China and is poised to surpass wind this

year to become the country's largest source of clean energy. Some 51 gigawatts of wind power was added from January to June.

Li Shuo, the director of the China Climate Hub at the Asia Society Policy Institute in Washington, described the plateauing of China's carbon emissions as a turning point in the effort to combat climate change.

"This is a moment of global significance, offering a rare glimmer of hope in an otherwise bleak climate landscape," he wrote in an email response. It also shows that a country can cut emissions while still growing economically, he said.But Li cautioned that China's heavy reliance on coal remains a serious threat to progress on climate and said the economy needs to shift to less resource-intensive sectors. "There's still a long road ahead," he said.

Power for 5m households

A seemingly endless expanse of solar panels stretches toward the horizon on the Tibetan plateau. White two-story buildings rise above them at regular intervals.

In an area that is largely desert, the massive solar project has wrought a surprising change on the landscape. The panels act as windbreaks to reduce dust and sand and slow soil evaporation, giving vegetation a foothold. Thousands of sheep, dubbed "photovoltaic sheep," graze happily on the scrubby plants.

NEWS BOX

Virat, you got to play some shots: Former Australia batter recalls sledging India star

New Delhi. (Agency)

Former Australia batter Joe Burns, who's currently leading Italy recently recalled how sledging Virat Kohli in 2014 backfired for his team. Burns made his debut against India during the third Test of the Border Gavaskar Trophy 2014-15 at Melbourne Cricket Ground (MCG).

He recalled how he planned to disrupt Kohli's confidence by asking him to play some shots in the middle of his innings. However, the comment backfired big time as Kohli made a sharp retort, reminding Burns that he was on his debut."I'm fairly certain Virat scored 100 that day. There was a little bit of chirp going on. Not sledging, just obviously we got Hadzi behind the stumps and Watto at first slip. Nathan Lyon was bowling, so I'm in close. I think it'd been four hours. I hadn't said a word. I think I said one line. I said to him, 'Virat, you got to play some shots'," Burns told Crictracker.Burns further mentioned that he understood his mistake and didn't say

anything for the next four days.

"He stopped the bowler, stopped Nathan Lyon, turned to me and said, 'You don't talk, rookie.' Next ball he faced up, smacked it through covers. It was very embarrassing for me. I didn't say a word the next four days after that, but it showed me that Virat was not someone to mess with," Burns said with a laugh.Kohli went on to play a marathon innings of 169 (272), smashing 18 fours in his knock. It was the then highest score for the India star in the longest format. He further scored 54 in the second innings to help India draw the match.He also smashed another century in the fourth and final Test of the series in Sydney and finished the rubber with a whopping 692 runs from eight innings at an average of 86.50 with four centuries. However, despite his stellar show, India lost the series by 0-2.

India vs Pakistan sporting ties: 5 big questions after new government policy

The India-Pakistan match at the Asia Cup is likely to go ahead following the government's new policy on hosting and competing in sports involving Pakistan. But it raises serious questions: should international sporting credibility come before national interest and security?

New Delhi. (Agency)

When the Asia Cup schedule was first announced, many were sceptical. Even with the fixtures out, people wondered whether the India-Pakistan match would actually go ahead, given the current geopolitical climate in the aftermath of the terror attack on Phalgam, Jammu and Kashmir. Then, when the Indian team for the Asia Cup was announced, doubts persisted—some believed it was still merely the BCCI's decision and that the government might withhold approval.But now, the picture is clear. Anyone who thought the India-Pakistan game in the Asia Cup would be called off due to public backlash has been proven wrong. This debate has been everywhere: on social media, in mainstream media, and even in Parliament, where questions were raised.The government has now issued an official statement, all but confirming that the India-Pakistan match will go ahead in the Asia Cup. They have also provided their reasoning, which in turn raises several questions. Before considering those questions, it is important to understand what the government has said regarding the clash.The first point is that, while India maintains no bilateral sporting ties with Pakistan, it will participate in international and multilateral tournaments involving Pakistan. This is consistent with India's long-standing stance: there has been no bilateral cricket with Pakistan since 2013, and that status quo remains. However, the government has now explicitly stated that India will play Pakistan in international and multilateral tournaments, including the Asia

Cup.The government notification further states that Pakistani players and teams will be able to participate in such multilateral events hosted by India.

"With regard to international and multilateral events, in India or abroad, we are guided by the practices of international sports bodies and the interest of our own sportspersons. It is also relevant to take into account India's emergence as a credible venue to host international sports events," the Sports Ministry stated."Accordingly, Indian teams and individual players will take part in international events that also have teams or players from Pakistan. Similarly, Pakistani players and teams will be able to participate in such multilateral events hosted by India," it added.This is not just about India playing Pakistan in these tournaments. The government has made it clear that even if Pakistani players wish to come to India for multilateral tournaments—such as the Asia Cup in hockey—they will be granted visas and allowed to participate. Let me emphasise: this applies to all sports, not just cricket. This advisory comes in the aftermath of the Pahalgam terror attack, which claimed 26 lives, and Operation Sindoor, India's retaliatory action dismantling terror infrastructure across the border.

Rahul Dravid recalls R Ashwin's YouTube video on batting against spin, jokes about backlash

New Delhi, . (Agency)

Former India cricketer and head coach Rahul Dravid teased Ravichandran Ashwin for indirectly helping Australia to play spin during the 2023 Test series between two teams. Ashwin had uploaded a guide to play spin in India during the 2023 Test series against Australia after India were 2-0 up in the series.However, after India lost the third Test in Indore, the video went viral, resulting in Ashwin facing backlash. Recently, Rahul Dravid recalled the incident and teased the former spin bowler for coaching the Australian team in Tamil in the middle of the series. He also revealed how he received some flak as people were like that he's coaching better than you.You even coached the Australian team. I got sent a clip. Unfortunately, it was in Tamil. So that's the one I've seen about you. You're speaking in Tamil and with a little bit of Tamil that I understand, you're coaching the Australian team in the middle of the Australian series, how to play spin. And I'm thinking, Ash, the series is not over . I know that you got the flak for it. The flak I got was

'Ashwin is coaching better than you are — what are you doing?,"said Dravid on Ashwin's Youtube Channel.Ashwin also recalled a hilarious conversation with Mitchell Starc during the third Test, who offered to teach him how to play a bouncer giving reference of his Youtube video."If I knew how to do that, I would have told our boys how to play spin. I mean, why would I go and tell the Aussies?. An interesting thing was that (Mitchell) Starc came and told me. I mean, he bowled a bumper, and I just left it in the Indore Test match. I think we were 80 for 7 or something. We went for lunch, and he was walking with me. He was like, 'Can I tell you how to play the bouncer like your YouTube video?It's good to know that Starc knows Tamil. I think it was maybe the Australian guys got some Tamil guy," said Ashwin.India went on to win the series by 2-1 as Ashwin was adjudged Player of the Series along with Ravindra Jadeja. The off-spinner scalped 25 wickets from four matches at an average of 17.28 with two five-wicket hauls to his name. On the other hand, Ravindra Jadeja was the second-highest wicket-taker with 22 wickets from four matches at an average of 18.86 with two five-wicket hauls.

India left-arm spinner Gouher Sultana retires from all forms of cricket

New Delhi. (Agency)

India left-arm spinner Gouher Sultana has announced her retirement from all forms of cricket. Sultana made her international debut during an ODI against Pakistan in 2008 and went on to represent the country in 50 ODIs and 37 T20Is. Her last appearance for the country came during the Women's T20 World Cup 2014 against Pakistan.She recently also featured in the Women's Premier League (WPL) 2024 and 2025 seasons, playing for UP Warriorz. The 37-year-old has finally announced her retirement through an Instagram post, where she called playing for India the greatest honour in her life."After years of wearing the Indian jersey with pride, passion, and purpose - the time has come to pen down the most emotional note of my cricketing journey. With a heart full of memories and eyes welled with gratitude, I announce my retirement from all forms of the game," Sultana wrote in an Instagram post announcing her retirement.

"To have represented India at the highest level - in World Cups, tours and battles that tested both skill and spirit - has been the greatest

honour of my life. Every wicket taken, every dive in the field, every huddle with my teammates has shaped the cricketer and the person I am today," she added.Sultana scalped 66 wickets from 50 ODIs at an average of 19.39 with three four-wicket hauls to her name, with best figures of 4/4. She further scalped 29 wickets from 37 matches at an average of 26.27 with best figures of 3/17.The Hyderabad-born cricketer played in two ODI World Cups, in 2009 and 2013, and picked up 12 wickets in 11 matches. She also featured in three T20 World Cups from 2009 to 2014, and claimed seven wickets. Sultana is currently a BCCI Level 2 coach.

Right after Asia Cup squad announcement, BCCI replaces 2 national selectors

New Delhi. (Agency)

The Indian Cricket Board (BCCI) is set to replace two of its national selectors, just two days after the announcement of India's Asia Cup squad, which saw the return of Shubman Gill and Jasprit Bumrah to the T20I fold.The BCCI has opened applications for two spots in the men's national selection committee. The selected members will be responsible for picking the Indian team across all formats — Tests, One-Day Internationals, T20 Internationals, and any other formats as determined by the BCCI.Who is Eligible for National Selector Positions?

Only cricketers with first-class experience are eligible to become national selectors. A candidate must meet at least one of the following criteria:

A minimum of 7 Test matches;

OR 30 First-Class matches;

OR 10 ODIs and 20 First-Class matches.

Additional eligibility requirements:

Must have retired from the game at least 5 years prior.

Must not have been a member of any BCCI Cricket Committee for a cumulative period of 5 years.Earlier media reports suggested

that the current selection committee — comprising Ajit Agarkar, SS Das, Subroto Banerjee, Ajay Ratra, and S Sharath — was under scrutiny. It was reported that changes to the panel could be made at the BCCI's Annual General Meeting (AGM) in September.According to a report in Hindustan Times, Sharath is likely to be replaced by former India spinner Pragyan Ojha. Sharath, in turn, is expected to take over as the chief of the junior men's selection committee.While two members of the senior men's committee are set to be replaced, Ajit Agarkar is likely to receive an extension on his tenure till 2026.

Asia Cup 2025: Abhishek Sharma gears up for his biggest test yet

BCCI has reportedly extended Ajit Agarkar's tenure as chairman of the senior men's selection committee till June 2026. This move comes after India's strong performances under his leadership, signalling stability amid upcoming cricketing challenges.

New Delhi. (Agency)

India have named swashbuckling opener Abhishek Sharma in their Asia Cup 2025 squad. For the first time, Sharma finds himself selected beyond a bilateral series — a clear show of faith in a player who has at times blown hot and cold in T20Is but carries an impressive pedigree.Indian selectors have generally shown reluctance to back outright aggressive batters in marquee tournaments. The belief merited results when India recalled Rohit Sharma and Virat Kohli for the T20 World Cup. While the recall did destabilise the continuity in the batting lineup, pushing

Rinku Singh, Yashasvi Jaiswal and Sanju Samson out of the team, it did bring home India's first T20 World Cup trophy in nearly 20 years.In the Asia Cup 2025 squad itself, the resurgence of Shubman Gill is intended to provide insurance for the batting order, in case things go wrong on the odd day. However, for now, Shubman's close friend Abhishek appears safe from those selection dilemmas.Currently ranked the No.1 T20I batter in the world, Abhishek has earned the trust of the selectors and team management for the value he brings at the top of the order.

The left-hander takes on the opposition's best bowlers, and when he gets going, he can completely unnerve the opposition.In a 17-match-old T20I career, Abhishek already has two hundreds and two fifties to his name. He boasts a strike rate of 193.84 — enough to make opponents uneasy from the very first ball. That said, all his performances so far have come in bilateral series, and competition cricket presents a different challenge. If India go all the way, they'll play seven matches in just 20 days — and that's where Abhishek Sharma will be tested. Can he continue to put pressure on bowlers in high-profile games? Can he grind out runs when things aren't going his way? These are the answers the selectors will be looking for at the Asia Cup 2025.

If Abhishek rises to the occasion, his place in India's home T20 World Cup squad next year is likely to be sealed.

Sanju Samson preparing for new Asia Cup role Keeper slots at No.5 in local league

New Delhi. . (Agency)

India T20I opener Sanju Samson slotted himself at the No. 5 spot in Kerala Cricket League. Playing in his first match of the tournament, Samson gave up his preferred opener's spot to Vinoop Manoharan and Jobin Joby of Kochi Blue Tigers, putting himself down in the lower middle order.

Samson, however, did not get to face a single ball in the innings, as Saly Viswanath's half-century helped the Tigers reach the required target of 98 runs in just 11.5 overs. The change in Samson's batting position has perhaps come due to the fact that he is at risk of being snubbed out of the opener's slot from India's Asia Cup side.The Kerala batter, who has opened for India in the last cycle, is likely to be removed from the opener's spot due to the return of Shubman Gill, who has once again been handed the vice-captaincy in the side.There are no openings at No. 3 and No. 4 either, as Tilak Varma and captain Suryakumar Yadav are locked into those places. Hence, it is likely that Samson, desperate to get himself into the playing XI as the preferred wicketkeeper-batter, is trying his luck at the No. 5 spot.

Samson has not batted much in the middle order position in T20Is. For the Indian team, he has played 5 matches in the No. 5 position and has scored only 62 runs at a strike rate of 131.91. In the Indian Premier League, he has batted only 3 times in that position and scored a total of 34 runs.Samson would need to prove his credentials in the Kerala Cricket League if he wants to retain his position in India's Asia Cup playing XI. He is in competition with Jitesh Sharma, who has played as a specialist finisher for Punjab Kings and Royal Challengers Bangalore.

In the 2025 season, Jitesh scored 261 runs in the lower middle order at a massive strike rate of 176.35.

India squad for Asia Cup T20: Surya Kumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (WK), Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (WK), Harshit Rana, Rinku Singh

Stand-bys: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal.

Sunny Leone

Turns Airport Into A Runway With Effortless Chic Look

Airports have increasingly become fashion runways, where celebrities showcase some of their best off-duty looks. Sunny Leone was the latest to grab attention with her casual yet chic travel attire. In a video shared by Instant Bollywood, the actress was seen arriving at the airport in a stylish ensemble that perfectly blended comfort with elegance.She opted for a fitted ribbed top in a warm brown tone, layered with an oversized, soft beige cardigan that gave her look a relaxed yet polished edge. Pairing the top with light-wash, wide-leg denim jeans, Sunny brought a laid-back charm to her outfit while still keeping it fashionable. Her accessories added just the right touch: oversized dark sunglasses and a spacious light-colored tote bag, possibly woven, that enhanced her relaxed vibe.

Her hair was styled sleek and straight, while her makeup remained minimal and natural. Although her footwear was not completely visible, her overall outfit suggested she paired it with something comfortable like sneakers or flats.

While her airport look caught attention, Sunny Leone is also going viral for another reason—her chartbuster track Pink Lips from the 2014 film Hate Story 2 is back in trend. The song, which became an instant hit upon release, has resurfaced on Instagram Reels. Users are now creating fun dance clips and edits with the catchy track, much to Sunny's surprise and delight.

Sunny Leone's Bollywood Journey

Sunny Leone has been a familiar name in Indian entertainment for over a decade. She first came into the spotlight as a contestant on Bigg Boss Season 5. Her appearance made her a household name, soon leading to her Bollywood debut in Pooja Bhatt's Jism 2 (2012).

Following her debut, Sunny went on to feature in films such as Jackpot, Ragini MMS 2 and Ek Paheli Leela, carving her space in the film industry. Beyond films, she has also become a beloved television personality, co-hosting MTV's hit dating reality show Splitsvilla, where her charm and wit won over young audiences.

Recent Work: Kennedy and Upcoming Malayalam Debut

Most recently, Sunny Leone starred in Anurag Kashyap's neo-noir thriller Kennedy, alongside Rahul Bhat, Mohit Takalka and Abhilash Thapliyal. The film garnered praise for its dark storytelling and gripping performances, further showcasing Sunny's growth as an actress willing to take on layered roles.

Natasa Stankovic

Proves Fitness And Fashion Can Glow Together

Natasa Stankovic recently served pure fitness vibes as she was snapped after her workout session. The Serbian dancer, model and actress was captured in a casual, sporty look outside a gym in Bandra, Mumbai, just a few hours ago. Besides her overall appearance, it was the diva's candid meeting and greeting session with the paparazzi stationed over there that captured much attention.

In a video posted on Instagram, Natasa Stankovic was seen leaving a gym premises in Bandra, Mumbai, while being stopped by the shutterbugs for some candid clicks. Dressed in stylish athleisure wear, the actress exuded a relaxed fashion sense. She was wearing a black sports bralette teamed with grey cycling shorts, which made her look every bit stunning.

Natasa Stankovic Hits The Gym In A Sporty Look

The fashionista layered her outfit with a bright lime green-hued jacket that added the perfect dollop of vibrance to her appearance. Keeping comfort as her ultimate priority, she teamed her appearance with minimal makeup, a messy ponytail hairdo, and a pair of white sneakers teamed with matching socks. However, it was her post-workout glow that was unmissable. She was also seen carrying her phone, a small bag for her essentials and a tumbler in her hand.

Fans Are In Awe Of Natasa Stankovic's Approachable Nature

The 33-year-old was seen engaging with the paparazzi, striking poses and greeting them warmly, reflecting her approachable and humble nature. The video was captioned as "Natasa looks pretty as she gets snapped in the town." Soon, social media users began showering the diva with love by flooding the comment section with appreciative emojis.

Natasa Stankovic's Professional Front

The diva made her debut in Bollywood in 2013 with her stint in the political drama titled Satyagraha. Directed by Prakash Jha, the movie featured the Serbian dancer in the dance number Aiyo Ji opposite Ajay Devgn. The following year, she participated in Bigg Boss 8, following which, she was also seen in Nach Baliye 9. Since then, Natasa enjoys a huge fan following on her social media handles and has been part of a number of Bollywood films and others.

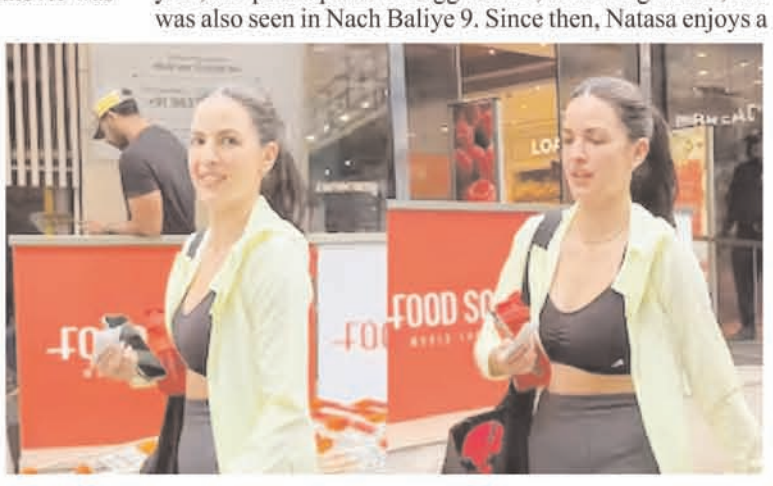

Coming to her personal life, she was married to Indian cricketer Hardik Pandya, and the couple was blessed with a son, whom they lovingly named Agastya. However, the couple mutually separated in July 2024 but continue to co-parent their child.

Vaani Kapoor's Pre Birthday Bash With Family Has Raashii Khanna's Attention

Bollywood diva Vaani Kapoor, whose birthday falls on August 23, has already started early celebrations with her family. Sharing a series of candid photos and a video on Instagram, the actress described the gathering as a special pre-birthday treat. The actress captioned the post, "Birthday love came early… from the best ones." Fans and colleagues flooded the post with birthday wishes and comments within hours.

A Family Affair

In the photographs, Vaani is surrounded by family members, who are smiling warmly and posing candidly with her. The actress also appeared glowing while posing with her parents, relatives and younger family members. The clicks showed the affection and closeness of the gathering as fans flooded the post with love.

Raashii Khanna and Sonam Bajwa were quick to respond. Raashii simply said, "Haha so cute Vaan," while Sonam left a line of heart emojis celebrating the friendship within the fraternity.

Fans Flood Social Media With Wishes

The post soon went viral as netizens appreciated the ordinariness of the celebration. Numerous fans showed enthusiasm for her birthday ahead, while others commended her for catching up with family before the day of celebration. Phrases like "Family love is the best gift" and "You look so happy, Vaani" filled the comments.The actress, who likes to keep her life personal and low-key, treated fans to a rare moment of family time, which was met with warmth.

On The Work Front

Vaani Kapoor is preparing for her upcoming projects. She will be seen in Wah Bhai Wah, directed by Shonali Rattan. The film is scheduled for release on December 18.Additionally, Kapoor will star in Abir Gulaal, directed by Aarti S. Bagdi, another highly anticipated project expected to release in 2025. Both films are considered important milestones in her career, showcasing her expanding range as an actress.

Payal Rohatgi On Post-Marriage Challenges: 'Haar Cheez Husband Se Poochna Padta Hai'

Payal Rohatgi talked about financial dependence after marriage, days after resigning from husband's charitable trust.

Payal Rohatgi has been in the news for her personal life. The actress, who is married to Sangram Singh, sparked speculation about a possible split after she resigned from the post of director of her husband's charitable trust, 'Sangram Singh Charitable Foundation'. Citing "personal reasons", she shared the news with her followers through an Instagram post.

While Sangram Singh later clarified that there is no trouble in his married life, putting all the rumours to rest, Payal has once again triggered a conversation online with a recent remark on the challenges women face post-marriage.

During a conversation with paparazzi, she opened up about her personal struggles to get back again to work and be independent.

She was heard saying, "It becomes very difficult for a married woman to actually get back again to work. You know because it's very important to work for a woman who has been independent. Magar shaadi ke baad husband se poochna padta hai, har cheez ke liye, har kharche ke liye. So that is something which is not in my DNA, but I am trying to get flexible." This comment hints at a potential rift in her marriage.

Sangram Singh on Divorce Rumours

Expressing that he and Payal would always be together, Sangram clarified in a statement, "There is no talk of divorce between us. We have been together for 14 years and will always be. I keep all my focus on doing good work. I do not pay attention to these talks of divorce, and I will also request her to not believe in such rumours."

He also addressed Payal's decision to resign from the director post. Sangram added, "This is Payal Ji's decision, and I respect her decision. Both of us have different approaches towards work. In such a situation, whatever Payal ji must have thought, she must have done it for the better. I wouldn't stop her. She is free to make her own decisions. There is no one wrong here. Every person is different."

Payal Rohatgi and Sangram Singh Marriage

After being in a relationship for several years, the couple tied the wedding knot on July 9, 2022, in an intimate ceremony in Agra. They have often been in the news for their personal differences.